more than Rs. 15 lakhs out of Rs. 85 lakhs which was sanctioned to purchase the accumulated stock.

In view of the serious situation that has arisen in the handloom industry in Kerala, I earnestly request the Government to take the following steps:—

1. Reservation in the manufacturing of handloom clothes.

2. Fix the price of all kinds of yarn used in the manufacture of handloom at least for a specific period, and ensure steady supply of yarn.

3. Introduce a national minimum wage immediately.

4. Make arrangements to purchase the accumulated stock and sell it through Government agency.

5. Prevent the rise in prices of essential chemicals which are used in the manufacture of clothes and set up a colour manufacturing unit at Cannanore.

(viii) NEED TO RESTORE TRAIN SERVICES ON DARJEELING HIMALAYAN SECTION OF N. F. RAILWAY

SHRI ANANDA PATHAK (Darjeeling): Under Rule 377, I am making a statement.

A serious situation has arisen since the unwarranted withdrawal of train services on the Darjeeling Himalayan Section of the N. F. Railway. Suspension of this service would throw a large number of railway employees out of employment and push them with their family members on the verge of starvation. As a consequence of suspension of this service a large number of tourists, who visit Darjeeling are experiencing great inconvenience. This is the tourist season and Darjeeling is one of the most beautiful tourist centres in the world. The economy of this backward hill region depends on tea, tourism and timber. The tea industry is dwindling and if the flow of tourists is also hampered due to withdrawal of this service, the whole economy of Darjeeling will collapse giving rise to serious economic, social and political problem. The transportation problem of the hills is very acute due to topographical position of the hills. The movement of small train on narrow gauge has contributed to some extent to ease this problem. Besides this, the small trains running on the narrow gauge on Darjeeling Himalayan section are themselves the unique objects of attraction. This is called Toy Train. This beautiful toy train was introduced a century ago by the then British Government. Britishers left India but the engineering genious of British engineers remained as an ornament of the queens of hills. Attempts were made to withdraw this service in the past but the public opinion forced the Government to retain this service. I, therefore, urge upon the Government to restore the train services on Darjeeling Himalayan section of N. F. Railway without any further delay.

14.24 hrs

DEMANDS FOR GRANTS, 1981-82—Contd.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of Ministry of Communications. Shri T. S. Negi.

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी गढ़वाल) उपाध्यक्ष महोदय, टेलीफोन के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि आज हमारे पूरे देश के हर एक शहर में जहां जहां टेलीफोन लगे हुए हैं, उनमें से शायद ही कोई ऐसा टेलीफोन होगा, जो चौबीस घंटे काम करता हो । कोई भी माननीय सदस्य यह बता दें कि क्या उसका टेली-

फोन ठीक ढंग से काम कर रहा है । मंत्रियों के टेलीफोन भी सही ढंग से नहीं काम करते हैं । मैं एक वाकया आपसे अर्ज करना चाहता हूं ।

माननीय संचार मंत्री के पी० ए० ने अपने टेलीफोन के बारे में इंजीनियर, टेलीफोन्ज को फोन किया । इंजीनियर टेलीफोन्ज ने फरमाया कि चूंकि दिल्ली की मशीनरी खराब है, इसमें कोई गड़बड़ है, इसलिए दिल्ली के टेलीफोन खराब हो जाते हैं । तो मंत्री जी के पी० ए० साहब कहते हैं :

Let telephones of Delhi go to hell, let my telephone be in order.

इनको अपने टेलीफोन की लगी हुई है, दूसरों की नहीं और मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि टेलीफोन नहीं चलता तो उस को बन्द कर दो । वह भी इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं । इस किस्म की हालत हमारे टेलीफोन सर्विस की है ।

एक निवेदन मुझे यह करना है कि पिछली सरकार ने यह तय किया था कि पहाड़ी इलाके में या जो ट्राइबल एरियाज हैं, इन सारी जगहों में हम व्यवस्था करेंगे कि टेलीफोन लाइन वहां मिला दी जाय । यह भी तय किया था कि जहां जहां थाने हैं, जहां जहां तहसीलें हैं, ब्लाक्स हैं वहां और ढाई हजार की पापुलेशन जहां है वहां एक पब्लिक काल आफिस खोला जायेगा । मैदानी इलाके में जहां पांच हजार की पापुलेशन है वहां कम से कम एक पब्लिक काल आफिस होगा । लेकिन यह सरकार तो ऐसा पता चलता है कि सो गई और इस काम को करने के लिए कतई तैयार नहीं है ।

एक निवेदन मेरा यह है कि जो निर्णय सरकार ने एक बार ले लिए उन को पूरा करना चाहिए । कम से कम पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि और कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है । अगर हम कोई फोन करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते क्यों कि टेलीफोन की व्यवस्था ही नहीं है । तो जो निर्णय हो चुके हैं कम से कम उन को तो पूरा करना चाहिए । कम से कम उन क्षेत्रों को आप टेलीफोन दीजिए जहां दूसरा कोई साधन नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां पत्र और चिट्ठियां 15-15, 20-20 दिन में पहुंचती हैं । इस की कोई व्यवस्था नहीं कि चिट्ठी जल्दी पहुंच सके ।

अगर कहीं टेलीग्राम भेजते हैं तो छः छः, सात सात दिन में टेलीग्राम पहुंच रहा है । इस मुल्क में यह व्यवस्था है संचार मंत्रालय की । टेलीफोन भी टाइम पर नहीं पहुंचते हैं । टेलीफोन हमारे पास तब आते हैं जब यहां मीटिंग हो जाती है, तब वह हम को मिलते हैं कि वहां मीटिंग है । यह मेम्बर पार्लियामेंट के बारे में और अपने बारे में बात कर रहा हूं । घूम घाम कर पत्र भी यहीं आ जाते हैं, टेलीग्राम भी यहीं आ जाते हैं ।

ईजतनगर अरुणाचल की राजधानी है । वहां टेलीग्राफिक दफ्तर खुल गया है । दिल्ली और बम्बई में वहां के लोगों ने शिकायत की कि वहां के लिए टेलीग्राम नहीं लेते । उन को पता नहीं है कि वहां टेलीग्राफ आफिस खुल गया है । यह खुद इतनी कमी इस विभाग के अन्दर है, इसकी जानकारी इनके विभाग के लोगों को नहीं है ।

एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो केजुअल वर्कर इस विभाग के अन्दर काम कर रहे हैं, विभाग का नियम

यह है कि जब वह 200 दिन काम कर लें तो उन को परमानेन्ट कर दिया जाय लेकिन उनको 200 दिन पूरा नहीं करने दिया जाता और बीच में ही एक दो दिन की सर्विस ब्रेक कर दी जाती है। वे पांच पांच, छः छः साल से काम कर रहे हैं लेकिन उनको परमानेन्ट नहीं किया जा रहा है। इस के बारे में डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए यह तो डिपार्टमेंट बढ़ रहा है, इस का एक्सपेंशन हो रहा है। तो जितने आज तक उस में कैजुअल वर्कर थे उनको सर्विस में ले लेना चाहिए। इसमें सरकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार तो बड़े जोरों से कहती है कि बेरोजगारी खत्म करेंगे, तो जो लोग थोड़े टेम्पोरेरी काम कर रहे हैं उनको पूरे तरीके से इस में क्यों नहीं लिया जाता ?

इस मुल्क में ई डी (एक्सट्रा डिपार्टमेंटल) वर्कर्स तीन लाख हैं। उनकी हालत ऐसी है कि उनको पूरे तरीके से तनख्वाह भी नहीं मिलती। वूथलिंगम कमेटी ने सिफारिश की थी कि इन लोगों को कम से कम आप मंहगाई भत्ता दें लेकिन मंहगाई भत्ता देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। जो पेंशनर्स हैं, उनको मंहगाई भत्ता मिलता है लेकिन ये लोग जो पांच घंटे कम से कम दिन में काम करते हैं उनको मंहगाई भत्ता नहीं मिलता। मेरी सिफारिश है और मैं मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा कि उन लोगों को कम से कम मंहगाई भत्ता मिल जाना चाहिए। पिछली जनता गवर्नमेंट ने उन की तनख्वाह बढ़ाई थी। अब कम से कम एक चीज मंत्री महोदय यह कर दें कि उन को डीअरनेस एलावेंस दे दें।

दूसरी बात यह है कि वे लोग काम कर नहीं सकते। उन के अन्दर जो आने जाने वाले हैं जो घूमते हैं और डाक बांटते हैं गांव-गांव में उन के पास बूट नहीं हैं, वर्दी नहीं है, उन को वह सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो परमानेन्ट लोगों को मिलती हैं। तो मेरा निवेदन है कि उन को वही सुविधाएं मिलनी चाहिएं। ऐसे लोग जो जगह-जगह डाक बांटते हैं, बड़े-बड़े ट्राइबल एरियाज में, ऐसे एरियाज में जहां जंगल हैं, जहां रेगिस्तान हैं, ऐसे स्थान हैं जहां पैदल चलना बहुत दुश्वार है, ऐसी जगहों में जा-जा कर जो डाक बांटने का काम करते हैं उन लोगों की सुविधाओं का ख्याल इस मंत्रालय को करना चाहिए। उन लोगों को इस मंत्रालय की ओर से सुविधा मिलनी चाहिए—ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

मेरा आपके द्वारा यह भी निवेदन है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जितने भी इस डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं उनको हिल-एलाउन्स मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों के अपने सभी कर्मचारियों को हिल-एलाउन्स दे दिया है लेकिन इस मंत्रालय ने अभी तक इस बात को नहीं सोचा—इस बात पर मुझे बड़ा अफसोस है। भारत सरकार को तो हर मामले में पहल करनी चाहिए। ऐसे विकट पहाड़ी क्षेत्रों में जो कर्मचारी जाकर रहते हैं उनको हिल-एलाउन्स तो मिलना ही चाहिए क्योंकि मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले वहां पर खाने की चीजों के भाव दुगुने-तिगुने रहते हैं और साथ ही वहां आने जाने की समस्यायें विकट होती हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी जब अभी यहां पर उत्तर देंगे तो उसमें हिल-एलाउन्स देने की घोषणा करेंगे।

मैं साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे टेलीफोन तो टेप होते ही हैं, साथ साथ मंत्रियों के टेलीफोन भी टेप हो रहे हैं। इसके अलावा

टेलीफोन्स के जो इतने लम्बे-लम्बे बिल आ जाते हैं उसकी भी आम शिकायत है । बढ़ाकर पता नहीं कैसे दो, तीन, चार हजार तक के टेलीफोन के बिल बना दिए जाते हैं । यह सारी शिकायतें हैं जिन पर ध्यान देकर सुधार करने की आवश्यकता है । ऐसे केवल दो ही मंत्रालय हैं—रेल मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय—जोकि डायरेक्टली लोगों को सुविधायें पहुंचाते हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सेवाओं में सुधार कीजिए ताकि जनता को सुविधा मिल सके ।

SHRI P. NAMGYAL (Ladakh): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you very much for giving me some time to speak on the demands for grants to the Ministry of Communications. I would like to speak a few words in support of the Demand for Grants.

I would like to bring to your notice, particularly some of the problems facing my constituency. As you know, my constituency is the biggest constituency in India comprising some 97,000 sq. Kms., in which we have only 2 Post Offices. By this you can just imagine how critical the problem is. People are living scattered all over the wide area of my Constituency and they have only two Post Offices. There are, of course, a couple of Branch Post Offices also. But their number is inadequate to cater to the needs of the entire population and we have got only 2 Telegraph Offices and that too do not work on Sundays and holidays. Because of this problem, I would like to request the hon. Minister for Communications through your good offices to take a special view of the problem in my area, in view of the strategic importance of that area; communication is the most essential part in that area.

I am grateful to the hon. Minister for Communications for introducing the Satellite communication system, by linking Leh with the rest of the country through the Satellite communication system. But I am sorry to say that that system is not working properly. The working hours are from 9.00 in the morning to 10.00 in the night. We heard initially that this would be in operation for 24 hours, hours, but actually it is not so. Most of the time we hear the complaint that, if a call is booked from here, the Operator at Delhi Centre says that the Leh operator is not attending; and if you go to Leh the operators there are saying that the Delhi operator is not attending. These are the problems which the hon. Minister should look into.

Besides that, some time back—I do not remember when exactly it was done—a wireless telephone-cum-telegraph system was set up in one of the remotest corners of Ladagh, known as Deskit in Nubra. One day the babuji locked up the machines and went away. So, far, these machines have not been put into operation again. I would request the hon. Minister to look into this. In spite of our repeated requests to the concerned officers at the regional level, so far thees machines have not been put into action again. Similarly, we have the problem of Zanskar, another remote area of the district. My request to the hon. Communications Minister would be to pay a visit to those areas, not to Leh, Kargil and other district headquaters, but to the interior of those areas, so that he may be in a position to see the problems we are facing there. Particularly the ex-servicemen due to lack of post office facilities, have to go to the two main post offices at Leh and Kargil for collecting their pension; and they can hardly go once or twice a year because most of the time these areas remain cut off from Leh and Kargil due to difficult terrain and blockade of roads on account of heavy snowfall. For that reason, my suggestion is to open at least a couple of more sub-post offices in places like Numbra and Changthang in Leh district and Zanskar and Batalic in Kargil district. To start with, four sub-post offices should be opened in these areas and subsequently the number should be increased because these four centres may not be sufficient to cater to the needs of the entire population

[Shri P. Namgyal]

there, including ex-servicemen. These are absolutely essential.

Then, I would like to say a few words about the workers, the service personnel of the P&T Department who are working in those remote corners of the country. You have to give some attention to their problems also. As some of my friends from the other side also have suggested, I support their view also that if you give some hill allowances or some incentives, they will be willing to go and serve in those remote areas. Otherwise, what actually happens is that people usually sent there from here are sent on punishment to our area and most of them—I would not say—are rogue but the people working in the telephone exchanges are so rude and their behaviour is so bad that most of the subscribers had surrendered their telephone in protest., wrong billing and so many other problems which are there. So my suggestion is that you should encourage and give adequate employments to the people living in those areas. We have sufficient number of candidates who are Matriculates and I think the minimum qualification is Matric for these posts. We have also got a number of ex-Servicemen. So you should give employment to these people in the telephone exchanges and the post-offices there. Whenever there is an employment opportunity, the local people have to go to Srinagar or Jammu for interview for these posts. This you will have to look into and see if you could have the interviews held at Leh or Kargil centres so that they could go to these centres and appears for the interview.

I would like to speak about their allowances. I think even for the whole of the Central Government employees working in Ladakh you have to look into it afresh so far as their compensatory allowances are concerned. Recently the Government of India has issued instructions to reduce the compensatory allowance from 35 to 25 per cent. But elsewhere you have gone on increasing the allowances—DA and other things. There you are doing the reverse thing. It is for the Central Government employees as a whole like the people serving in the Information Department, Radio stations, etc. and there are so many other people serving in the para-military forces like the MES, Canteen Service and so many other services. You have to see so that the Compensatory allowance which was previously 35 per cent with a certain ceiling is restored. There you have to sort out the total emoluments in consultation with the State Government. Actually, the State Government employees are getting more in Leh because of the High Altitude Allowance and the higher compensatory allowance and there too, without a ceiling. If a person is getting Rs. 100 as basic pay in Leh, then during winter he gets in some places 100 per cent allowance. that is; Rs. 200 extra plus DA. During summer 75 per cent. Similarly in some areas it is 50 per cent. In the case of Central Government Service Personnels you provide only 15 per cent of the allowances and that also is now reduced to 25 per cent with a certain ceiling. So you have to look into it so that the whole structure is examined afresh and these people are given adequate financial assistance and they may be able to work there willingly. Otherwise, they always try to go back. If there is a complaint, they feel happy because they are sent back to Srinagar or Jammu and in Srinagar, Jammu and other places you give them city allowance, housing facilities and many other facilities. In terms of the total quantum of money they get more in Srinagar and Jammu than a person posted in Leh.

So, with these few words, I request the Minister of Communications again to look into all these problems and take a sympathetic view to the problems of those people living in the remote hilly areas.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mhalgi.

*SHRI R. K. MHALGI (Thane): Mr. Deputy Speaker, Sir, the Report of the Ministry of Communications of 1980-81 which has been circulated to the Members, contains a very bold statement on page No. 1, which I would like to quote:

> "The Ministry of Communications has been able to achieve an all-round progress in almost all the activities and projects under its administrative control."

This is the one Department of the Government of India which concerns the common man and to know the pulse of efficiency of Administration and it is interesting to note the reactions of the people towards its activities and achievements. Not to speak of the common people, the Prime Minister herself felt constrained to remark on the 3th of last montn when she visited Bhusaneshwar, according to the Times of India of 31st March, 1981:

> "The Prime Minister, Mrs. Gandhi, was visibly upset over the erratic functioning of the Postal and Tele-Communications Service in Orissa when a memorandum with a number of delayed telegrams and letters was presented to her by Dr. Radhanath Rathi, editor of the Samaj", an Oriya daily at a press conference here yesterday.
>
> "A letter from Pune to Dr. Rath at Cuttack had taken 24 days and an express telegram from Patna to New Delhi had taken more than a week to arrive."

Mr. Tripathi the former Minister of Railawys resigned last year when the Prime Minister made some remarks about the functioning of his Ministry. But Mr. Stephen has not followed suit: well, it is for him to decide whether he should show the same self-respect which Mr. Tripathi had shown. The above example, however, points out the efficiency with which Mr. Stephen's Ministry has been functioning.

The Indian Telegraphs Act, 1885 and the Indian Post Office Act, 1898 govern the functioning of the Ministry of Communications. The first act has 15 amendments and the second one as many as 47 amendments upto now. Out of the 15 amendments to the first Act, the last one was made in 1974 and in six years there have been no amendments. The most of the amendments to the Indian Post Office Act have been made through the Finance Acts or adaptation legislation. There have been really only 10 amendments in 42 years in this Act. These Acts were made by the British Foreign Rules who had not sense of social obligations and made for their purpose in view, arrangements for the urban areas and neglected the rural communities. But after Independence both the laws should have been revamped to meet the needs and aspirations of the Indian villages. That has not yet been done. I hope that a comprehensive Bill to cover the above two Acts would be brought soon to delete the out-dated provisions and to provide the modern needs for Indian people.

Out of the total 239 cut motions moved on the demands of Grants for this Ministry, I take credit for 43. I may not be able to speak on all of them due to paucity of time but I hope that all the points that I make are answered properly so that I can tell my constituents what the Government of India propose to do.

Some commemorative permanent stamps have been issued on the great men of India, like Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru. I hope that the Government would not forget Chattrapati Shivaji. It would be only befitting if we honour that great son of India whom the Prime Minister eulogised recently at Raigarh in Maharashtra. All the countrymen want it and I hope that the Government will listen to them and issue a permanent postal stamp of Shivaji Maharaj.

*The original speech was delivered in Marathi.

[Shri R. K. Mhalge]

My congratulations to the Minister for not having increased the price of the post cards which are used mostly by the poor. Post card is a messenger of a poor man. The size of the post-cards should be maximised so that the users can make the maximum use of the postal facilities. Privately one may have of standard maximum size of postcard but the Government has limited its size to minimum. It must be increased.

The postal department is there for the good of the society, it is a social utility service, and revenue considerations should not encumber its style.

Delivery of letters on Sundays which was a regular feature earlier has been stopped. It should be recommended, even if it means a little more expenditure for the Department. The Department is a public utility service and should be run as such and not treated as a commercial concern.

Articles of postal stationery are in short supply for a part of the year. The Minister should give details of the shortage and inform the House the steps that the Government proposes to take to remove the shortage next year.

I have seen press reports that certain concessions for night telegrams and night telephone calls are proposed to be withdrawn. I hope that the Government do not execute this decision, if it has been taken. Please do not venture to do so.

My constituency comes under the Bombay Telephone Zone. The new telephone exchange at Kalwa connects Belapur industrial area in my constituency and the people there have to come through the Kalwa exchange instead of having a direct link with Bombay. Trunk call charges are to be paid. This should be discontinued and direct link with Bombay established. From the example of Kalwa Exchange there is fear in the minds of Thane subscribers that Thane shall be connected to New Mulund Exchange and would be cut off from Bombay. The projected move in that direction would be resisted with all the might at our Command, let me give a note of warning to that effect.

The EDA staff are treated as casual workers, but all types of work is expected of them. They should be treated like regular employees of the Department and the injustice being done to them since long now removed.

In answer to a question of mine about the shortage of the employees in Maharashtra Postal circle I was told that the information was being collected. It shows the negligent attitude of the Government.

I happened to visit a post office in my constituency, Shahapur, where a post has been lying vacant for the last seven months. It was held by a Lady employee, she had to go on long leave earlier, it is all right to the Department should have ensured that the postal service does not suffer in the process.

The Ministry of Communications in this budget appears to have done better in the matter of provision of quarters to the staff as compared to previous years. For that the Ministry deserves praise.

In reply to a question in the other House about the parallel post offices being run in the country, the Government said that they were looking into the matter. I hope that the Minister in his reply will tell the House the truth about this.

श्री मनोराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त, श्री स्टीफन, जब यहां विरोध पक्ष में बोलते थे, तो मेरी उन पर बड़ी श्रद्धा थी। वह एक अच्छे संसदीय आदमी हैं, और विरोध में बैठ कर वह देश का अच्छा प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है यह बात कहते हुए कि

अच्छा वकील, अच्छा पढ़ा-लिखा आदमी, अच्छा बोलने वाला, मगर इतना निकम्मा वजीर दुनिया की किसी सरकार में नहीं होगा, जितने डाक तार के वजीर, स्टीफन साहब, हैं । यह न समझें कि यह बात कहने में मुझे कोई खुशी हो रही है । मैं खुद की, अपने एक मित्र की, निन्दा और बुराई कर रहा हूं ।

मैं इस देश का मुकाबला अमरीका से नहीं करता हूं, जिसने आज से छः वर्ष पहले चांद से बातें की थीं । मैं रूस से भी मुकाबला नहीं करता हूं । मैं भारत की बात कहता हूं । याद रखें कि यह डाक-तार और टेलीफोन अभी तक भारत का नहीं है । भारत में ज्यादा से ज्यादा 30, 32 करोड़ आदमी हैं, जिनका इस महकमे से सम्बन्ध है । ज्यादा से ज्यादा दस करोड़ आदमी हैं, जो रोज, या कभी-कभी, या साल छः महीने में टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं । दस करोड़ वे हो सकते हैं, जिनको कभी-कभी तार नसीब हो जाता है । और दस करोड़ उन लोगों को भी मिला लीजिए, जिनका तार और टेलीफोन से तो नहीं, कभी-कभार, साल छः महीने में, चिट्ठी से सम्बन्ध हो जाता है । ये सिर्फ तीस करोड़ आदमी हैं । इस तरह स्टीफन साहब देश के कुल 66 करोड़ आदमियों के मंत्री नहीं हैं ।

आदिवासियों, पहाड़ों, गांवों और जंगलों में रहने वाले लोगों को इस विभाग से कोई लाभ नहीं होता है । जैसे पहले कबूतर कोई संदेश या चिट्ठी ले कर राजा के घर जाता था, उसी तरह आज डाक-तार विभाग की सुविधायें कुछ थोड़े से लोगों के लिए ही हैं । अगर सही माने में कोई कायदे का शासन हो, तो स्टीफन साहब पर मुकदमा चले । उन्हें पैसा किस बात का दिया जाए ? उल्टे उनसे हर्जाना लेना चाहिए, क्योंकि टेलीफोन खराब रहते हैं । डाक तार विभाग देश के एक भाग को दूसरे भाग के साथ जोड़ता है । उससे देश की एकता बढ़ती है, लोगों को शिक्षा मिलती है । क्यों चांद पर बैठ कर टेलीफोन से यहां बात की ? इस लिए कि दूसरी दुनिया इस दुनिया से मिले । उसी तरह इस तरीके से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है ।

लेकिने स्टीफन साहब अपने देश को भी जोड़ नहीं सके हैं, और शायद यह उनके बस की बात भी नहीं है । कुछ वह पुराने हो गए हैं, कुछ मशीनें पुरानी हो गई हैं । इस विभाग का काम आधुनिक तरीके से नहीं चल रहा है । मशीनें खराब हैं, टेलीफोन खराब रहते हैं, तार-घर में खराबी है, तार पहुंचाने वालों को कोई सुविधा नहीं है । जंगलों और पहाड़ी इलाकों में ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन वहां पर काम करने वालों को तनख्वाह कम मिलती है । जो दिल्ली में रहते हैं, उनको ज्यादा पैसा और सुविधायें मिलती हैं । स्टीफन साहब बुरा न मानें, अच्छा हो कि वह इस विभाग को छोड़ दें, कोई और विभाग सम्भाल लें । वैसे वह कामयाब आदमी हैं, दिमाग रखते हैं, अच्छा बोलने वाले आदमी हैं । लेकिन कभी कोई दवा किसी रोग के लिए ठीक नहीं बैठती है । टेलीफोन को कैन्सर हो गया है, तार को सिन्निपात हो गया है और टिकटों को लकवा मार गया है । इन तीनों की बीमारी का इलाज कहीं नहीं है ।

इस लिए मंत्री महोदय इस बारे में कुछ करें । गांवों, जंगलों, पहाड़ों और आदिवासी इलाकों में डाक-तार की सुविधायें ज्यादा बढ़ाई जायें । अगर वह समाजवादी विचार रखते हैं, तो वह वेतन

और सुविधाओं के फर्क को कुछ कम करें, बड़े और छोटे की तनख्वाह और सुविधाओं के फर्क को कम करें । गांवों में डाक-तार की सुविधायें बढ़ाई जायें । मिसाल के लिए हरियाणा में एक गांव है शेरपुरा । उसकी 1500 की आबादी है, लेकिन वहां डाकखाना नहीं है । पहाड़ी इलाकों में डाकखाना और तारघर नहीं हैं । मंत्री महोदय जो कुछ कर सकते हैं, वह करें । मैं तो स्टीफन साहब को राय दूंगा कि दोस्त, कोई और अच्छी दुकान देख लो—यह दुकान तो नाकारा हो गई है—, ताकि कामयाब हो । तुम्हारी नाकामयाबी से मुझे खुशी नहीं है बल्कि ईमानदारी से तकलीफ है । तुम अच्छे आदमी हो, अच्छी जगह बैठते तो कुछ काम हो जाता । यह घाटे की दुकान है । इन्दिरा सेठ से कह दो कि यह दुकान किसी और को दे दे, मैं कोई और दुकान चला लूंगा ।

DR. KRUPASINDHU BHOI (Sambalpur): I rise to support this Demand for the Ministry of Communications from the depth of my heart. I wish to make some points for the consideration of the Ministry of Communications. Of course, I am not placing any tall claim on the tallest Minister of this Cabinet; but I will try to enumerate the difficulties which the Department of Communications is facing, and to ventilate the grievances of the people as a whtle.

We are in the era of satellites; and we are boosting satellite communications internationally. But we are not creating confidence in the minds of our people, because more than 1300 towns and cities are yet to be connected with automatic exchanges. Even now they are manual exchanges. 148 districts are yet to be connected with automatic exchanges.

Whenever any question is asked in Parliament in this connection, the Minister replies that due to financial constraints they are not able to automatize the manual exchanges—i.e. convert them into automatic exchanges. But I have to point out something: Demand No. 18 for 1980-81 deals with the capital outlay on Posts and Telegraphs. The previous budget estimate was for Rs. 451.59 crores, but the revised estimate has slided down to Rs. 410.96 crores. So, there is a shortfall of Rs. 40.63 crores; and the explanation given by the Department is that it is due to slippage in supply of stores, and shortfall in telecommunication inputs If there is an implementation gap, nobody is responsible.

About automatization of the exchanges throughout the country, the Minister has assured us that it will be done by 1990, i.e. that we will be able to automatize the exchanges at least in the district headquarers. I hope the Minister will look into the matter very seriously, and find out why these things are happening. There are complaints throughout the country in respect of local calls, trunk calls and STD calls. Failure in the case of local calls, is 8 per cent, as against the standard of 2 per cent. In respect of trunk calls, the failure is 40 per cent, as against the standard of 10 per cent. The failure is 70 per cent in respect of STD calls, whereas the standard is 10 per cent.

What are the diseases afflicting the Department due to which the Minister is unable to eradicate this type of shortfalls? Is it the view of the Department that they should "repeat the mixture till the patient dies"? The failure in respect of STD calls is 70 per cent. Will the officers of the Department be satisfied if it is 100 per cent? The reasons for this failure should be found out and eradicated. According to Mr. Bagri, the disease is cancer. It is not cancer. But if the Minister will diagnose the diseases and amputate the gangrenous portion, then we should definitely re-constitute the Department of Communication and give it a better administration

What are the reasons for the poor performance? They are very poor maintenance, negligence by the staff

non-availability of spares as also insufficient and out-dated machinery. There is also lack of zeal and sincerity in the departmental employees. There is clash between the staff unions and the officers This should not be exposed to the people. The consumers should not face difficulties due to lack of confidence in the officers. So, what are the remedial measures? In which way should we manage this Department?

Now, 25 lakh telephone connections have been installed in the country and each year the waiting list is increasing by 3/4 lakhs. Now, more than 7 lakh people are waiting to get telephone connections. What will be the remedy? Our installed capacity for producing telephones is nearly 2 lakh per year. Of course, we are producing 2 lakh telephones. But there is a gap between the demand and the production. So, there will be an cumulative gap year by year.

A decision has already been taken to install a telephone industry in Bhubaneswar. The site has been earmarked by the State Government. According to the Minister, they are going to make a review for a separate site It means again a gap of another two years will remain and again the queue will be increasing day by day. Let us not forget that. We must take a decision immediately on the lines decided by the previous government.

In the line stores, public sector and the private sector undertakings are there, but still we have to import the material for the Telephone Department. We may import technology, technique, design and the paramter, but not the equipment itself. In the last five years, the Government have spent more than Rs. 150 crores on this. I do not criticise the import policy. We should import only the design and the paramter and not the equipment.

Modernisation and expansion is the modern dialogue of the day. So, why not we switch over to the electronic industry? Japan, Saudi Arabia and other countries have developed technology in this field and their telephone industries are running in a very cheaper manner.

Now I will come to organisation. Now everything is centralised. Why not we think of decentralisation? Why not the small matters like local organisational developmental and other matters be decentralised to the remotest places like district headquarters and State headquarters? At the same time, this is a very bulky Department. More than 8 lakh workers are working in it. So, there is no relation between the Postal Department and the Telecommunications Department; it is not interrelated. Why not bifurcate it and have a separate directorate? This is the second largest undertaking under the Government of India. More than Rs. 400 crores are spent in a year. Why not we have a separate or a board like the Railway Board so that the board should work independently and take decisions like autonomous bodies? There should be a separate budget like the railway budget. Why should it be an unwarranted addendum to the general budget?

Everybody has spoken about the remarks of Mrs. Indira Gandhi in Orissa. The Minister has taken a very immediate stand on this. He has, of course, in Orissa a right to eradicate the cancer cell which was there. I must congratulate him for his early action. At the same time, I will suggest a few more points so that my speech will be complete. There is always a quarrel between the staff union and the officers. The officers due to chaotic conditions in different parts of the country lack self-confidence and the extra departmental employees. At the same time, their union makes a tall claim to the Department so that the officers are not feeling self-confident. The officers are, therefore, not feeling self-confident. They were feeling self-confi-

[Dr. Krupasindhu Bhoi]

dent in 1975-76, but later on they have been de-moralised. I urge upon the Minister to see that the top ranking officers in Delhi go there and see the difficulties of the people there. Orissa, I want to say, has been treated as a punishment area. Whenever an officer from Delhi has to be transferred within twenty-four hours, he is transferred to Orissa. If there are any complaints against any officer like a Joint Director or somebody, he is also sent to Orissa. I want to request the Minister that if there are any complaints against any officer, a proper investigation should be made and severe punishment should be inflicted. They should even be dismissed, if necessary, to serve as an example to other officer. The Government can then, even recover the losses incurred during the last three years.

I want to mention another point about Orissa. The staff posted there are not willing to serve the people. The consumers have been in the queue. People have paid more than Rs. 5,000 each in certain localities for getting a telephone connection. People are not aware of the technicalities involved. I suggest that a refresher course for the officers serving in the State may be introduced as the State headquarters. If those officers are still not up to the mark, they should be given some other job, but they should not be shifted from one post to another.

Last but not the least, I again urge upon the Minister about the problems in my State, that is Orissa. Those problems are firstly that the Sambalpur-Cuttack microwave station which was sanctioned 12 years back is still given a low priority in the schemes of the Department. Another point which I want to make is, Sambalpur, from where I hail, and several other district headquarters and important towns in the State are still having only manual exchanges. Only one district is connected with an automatic exchange and all the other 12 are still being manned by manual telephone exchanges. This shows the regional imbalance that exists. In Maharashtra only seven towns are having manual exchanges, and all the other towns are having automatic exchanges. Thus Orissa State is being given step-motherly treatment. At least during the Sixth Plan period all the district headquarters should be provided automatic exchanges. There should be no dearth of the equipment to convert those telephone exchanges into automatic telephone exchanges. A decision was taken by the previous Government to locate a telephone industry in Bhubaneswar. That decision should not be shifted and the telephone industry should be located at Bhubaneswar.

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस डिमाण्ड का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत लम्बे अर्से के बाद इस डिमाण्ड पर पार्लियामेंट में बहस हो रही है । मुझे यह खुशी और ज्यादा होती, जैसे कुछ माननीय सदस्य ने इस विभाग की अहमियत को देखते हुए, इस के महान कामों को देखते हुए, इस के बड़े बजट को देखते हुए कहा--इस का अगर सैप्रेट बजट होता जिस तरह से रेलवे का है तो निश्चित तौर पर लोगों की जो बहुत लम्बे अर्से से शिकायत थी, वह दूर हो जाती और जो बहुत सारी त्रुटियां हैं, गड़बड़ियां हैं उन को दूर करने में और आप जनता को इस विभाग के जरिये ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने में सहूलियत होती ।

मैं जहां तक समझ पाया हूं--इस विभाग के तीन मुख्य उद्देश्य हैं:

(1) To provide efficient postal and tele-communication facilities at economic rates.

(2) to plan the development of postal and tele-communication system to meet the needs of the country;

(3) to make available postal facilities to the maximum of the public at large.

लेकिन, उपाध्यक्ष जी, इन तीनों उद्देश्यों का यदि तुलनात्मक दृष्टिकोण से विवेचन किया जाय तो ऐसा पाया जायगा कि यह विभाग इन उद्देश्यों की पूर्ति करने में, इस को जो वांछित सफलता मिलनी चाहिये थी, उस में यह असफल रहा है और यही वजह है जैसा कि अभी कुछ माननीय सदस्य ने कटक की चर्चा की। जब खुद इस सवाल पर प्रधानमंत्री जी इस विभाग के कामों से सन्तुष्ट नहीं हैं तो कोई वजह नहीं है कि प्रधान मंत्री जी के मातहत काम करने वाले कैबिनेट मिनिस्टर, इसे गंभीर न मानें। जहां तक उन की योग्यता का सवाल है, दक्षता का सवाल है, उन के पुराने होने का सवाल है— उसके बारे में कोई दो रायें नहीं हैं लेकिन डेमोक्रेसी में या किसी डेमोक्रेटिक कन्ट्री में जो सरकार में काम करता है उस के मारल का यह तकाजा है कि जब उस देश की प्रधान मंत्री इस तरह की बात उस विभाग के बारे में कहें, तो जैसा रेलवे विभाग में हुआ, त्रिपाठी जी ने रिजाइन किया, तो यहां भी यह औचित्य था, स्टीफ़न साहब एक बहुत ही सेल्फ़-रेस्पेक्टिंग मिनिस्टर रहे हैं, पता नहीं अब तक उन्होंने रिजाइन क्यों नहीं किया ?

मैं इस मौके पर विशेष रूप से बिहार राज्य की चर्चा करना चाहता हूं—बिहार राज्य की इस विभाग द्वारा घोर उपेक्षा हो रही है। आप बिहार राज्य में डाकघरों की तादाद को लें— 5581.7 आदमियों पर एक डाकघर पड़ता है, जब कि पूरे हिन्दुस्तान की औसत 4000 आदमियों पर एक डाकघर है की है। महाराष्ट्र में 4586.6 आदमियों पर एक डाकघर है, तमिलनाडु में 3567 आदमियों पर, राजस्थान में 2512 आदमियों पर, आन्ध्र में 2773 आदमियों पर, हिमाचल प्रदेश में 1536 आदमियों पर, डाकघर स्थापित हैं। डाकघर स्थापित करने का इन का जो क्राइटेरियर है— उसके अनुसार 2 हजार की आबादी पर डाकघर दिया जाता है, उस के साथ कुछ अन्य शर्तें भी हैं। यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो बिहार में लगभग 5500 की आबादी पर एक डाकघर है। इस से स्पष्ट हो जाता है कि बिहार राज्य की इस मामले में कितनी उपेक्षा की जा रही है....

प्रो० मधु दण्डवते : आप के यहां खत कम लिखते होंगे।

श्री विजय कुमार यादव : बिहार में खत कम लिखते हों, ऐसी बात नहीं है। इस समय जो क्राइटेरिया तय है उस के अनुसार यदि 3 किलोमीटर के भीतर कोई दूसरा पोस्ट-आफिस नहीं है तो वहां नया पोस्ट-आफिस दिया जाता है। लेकिन बिहार में डिस्टेन्स की एव्रेज क्या है ? 17.2 किलोमीटर पर एक पोस्ट आफिस आता है। दूसरी जगहों पर क्या स्थिति है— दिल्ली में 2.8 किलोमीटर पर, तमिलनाडु में 11.2 किलोमीटर पर, पंजाब में 13.6 किलोमीटर पर, केरल में 8 किलोमीटर पर—इस तरह से है। बिहार में 17.2 किलोमीटर पर एक पोस्ट आफिस आता है।

इसी तरह से टेलिफोन के सम्बन्ध में भी स्थिति है। टेलिफोन के सम्बन्ध में भी बिहार काफी नेग्लेक्टिड है। मैं इनके सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दे करके दूसरी बातों को लूंगा। बिहार में कालका

एक्सचेंज 65 हैं जबकि गुजरात में 137, महाराष्ट्र में 157, कर्नाटक में 130, आन्ध्र में 127 और तमिलनाडु में 76 हैं । स्वचल एक्सचेंज बिहार में 233, गुजरात में 431, महाराष्ट्र में 570, कर्नाटक में 533, आन्ध्र में 993, तमिलनाडु में 703 हैं। इसी तरह से टेलेक्स को भी हिसाब-किताब है । इस मामले में भी बिहार की काफी उपेक्षा की गयी है ।

पूरे देश में हमारे जो टेलीफोन की स्थिति है, उसके सम्बन्ध में मैंने कंसलटेटिव कमेटी की मीटिंग में शिकायत की है । मैंने अपनी कांस्टीच्युएंसी के लोकल टेलीफोन एक्सचेंज के सम्बन्ध में शिकायत की हैं । वहां की मशीनरी और करप्शन के सम्बन्ध में शिकायत करता रहा हूं । इस डिपार्टमेंट के अन्दर जितना बड़ा करप्शन है उसके सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय को कह चुका हूं कि मैं इसको साबित करने को तैयार हूं अगर आप एक हाई पावर जांच कमेटी बिठा दें तो । मेरा क्षेत्र बिहारशरीफ है । नालन्दा मेरी कांस्टीच्युएंसी है । वहां हिन्दुस्तान का अत्यधिक आलू पैदा होता है । वह व्यापार का एक बड़ा केन्द्र है और वहां लोगों को टेलीफोन के मामले में बड़ी दिक्कत होती है । बगैर पैसा लिये हुए कोई ट्रंक काल नहीं मिलता है । अगर पैसा दे दीजिए तो एक मिनट में ट्रंक काल मिल जाएगा । इसकी चर्चा मैंने मिनिस्टर साहब और इनके आफिसरों के सामने की है और कहा है कि आप अगर सूचना दिये वहां चलिये और मैं आपको इस बात को साबित करा दूंगा ।

15.32 hrs.

[Mr. Chintamani Panigrahi in the Chair].

इस तरह का भ्रष्टाचार लोकल एक्सचेंजों पर ही नहीं है, दिल्ली में पार्लियामेंट के मेम्बरों के साथ भी ऐसी स्थिति है । मुझे जब से टेलीफोन मिला है तब से वह खराब है । मैंने दर्जनों बार शिकायतें कीं, शिकायत पर मिस्त्री आया, लेकिन फिर टेलीफोन खराब का खराब । इसमें कोई सुधार नहीं होता । यह स्थिति तो टेलीफोन के मामले में है ।

डाक तार विभाग के सम्बन्ध में दूसरे लोगों ने भी बात की है । हर बजट में टेलीफोन और डाक तार न दो विभाग में आम जनता पर बोझा डाला जाता है । इससे चीजों के दाम बढ़ते चले जाते हैं । इस तरह से आप आमजनता पर बोझ डालते चले जाते हैं । इस बोझा डालने के बावजूद इस डिपार्टमेंट के अन्दर जो काम करने वाले हैं उनकी जायज मांगों को भी आप नहीं मानते । मैं नहीं कहता कि उनकी सभी मांगों का मान लिया जाए । मगर जो उनकी जायज मांगें हैं उनको तो माना जाए । इस विभाग के अन्दर जो विभागेतर कर्मचारी हैं उनकी तादाद लगभग दो ढाई लाख से ऊपर है । उनकी लम्बे अर्से से यह मांग रही है कि उनकी सेवाओं को रेगुलराइज किया जाए । इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों से आप टेम्प्रेरी सर्विस कंडीशंस पर काम तो ले रहे हैं । उनकी जो यह जायज मांग है उसको भी आप नहीं मान रहे हैं । आप के यहां स्टाफ की बहुत कमी है उस कमी को भी आप पूरा नहीं कर रहे हैं । कम से कम इस डिमाण्ड पर तो आपको सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए ।

मैं एक-दो सुझाव दे कर समाप्त करूंगा । मेरे ये सुझाव पूरे देश के लिए हैं । अभी आपने जो नये पोस्ट आफिस देने का सिद्धान्त तय किया है उसके बारे में हमारी बराबर मांग रही है हमारे पार्लियामेंट के माननीय सदस्यों की ओर से भी कि इस सिद्धान्त में थोड़ी ढिलाई होनी चाहिए ।

अभी जो आपने गांव की आबादी का क्राइटेरिया तय किया है उसमें आप मेन गांव की आबादी को ही गिनते हैं । मैंने गांव का जो एडजोयनिंग गांव है उसकी आबादी को उसमें नहीं गिनते । मेन गांव के साथ आपको एडजोयनिंग गांव की आबादी को भी गिनना चाहिए । दूसरे तीन किलो मीटर के स्थान पर आपको दो किलो मीटर की दूरी का सिद्धान्त बनाना चाहिए । इसके साथ जितने भी ग्राम पंचायत के हेड क्वार्टर हैं वहां आपको पी०सी०ओ० देने चाहिएं अंचल हेड क्वार्टर्स को एक्सचेंज और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को आटोमेटिक एक्सचेंज देने चाहिएं । हर अंचल को जिले से हर जिले को राज्य की राजधानी से आपको सीधे जोड़ना चाहिए । इस सिलसिले में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नालन्दा एक हिस्टोरिकल जगह है । पूरे देश से वहां पर लोग आते हैं । बिहार शरीफ डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर है । इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर आटोमेटिक एक्सचेंज की जो मांग काफी अरसे से चली आ रही है उस मांग को पूरा किया जाए । इसके बारे में मैं पहले भी मिनिस्टर साहब से कह चुका हूं और कई बार मिटिंग्स में भी इस बात को उठाया है । मंत्री महोदय से मेरा पुनः अनुरोध है कि इस पर जल्दी विचार किया जाए । आप कहते हैं कि फासिटी आफ फण्ड है कभी कहते हैं कि सामान की कमी है लेकिन डेवलपमेंट का काम तो होता ही है इसलिये पैसे की कमी के बावजूद डेवलपमेंट के काम में बिहार शरीफ जो कि नालंदा जिले का हैड-क्वार्टर है इसको टेकअप करें और आटोमेटिक एक्सचेंज देने की कोशिश करें ।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर (खण्डवा) : सभापति महोदय संचार विभाग की जो मांगें प्रस्तुत हुई हैं उन मांगों का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

सभापति महोदय हमारे देश में संचार विभाग ने एक मोनोपाली बना रखी है जिस प्रकार से किसी बिजनिस में किसी आदमी को प्राफिट होता है तो वह आगे एक्सपेंशन करता जाता है उस प्रकार से यहां नहीं चल रहा है । आज हर जगह से टेलीफोन एक्सचेंज की मांग आती है, चाहे शहर हो या गांव हो हर जगह यही मांग है कि लाइनें बढ़ाई जाएं । ओ० बाई० टी और दूसरे जो निथम हैं, उनके अंतर्गत टेलीफोन की मांग बढ़ती जा रही है और यदि उसकी पूर्ति नहीं करते हैं तो आप जानते हैं सभापति महोदय, कि चीजों के भाव बढ़ जाते हैं और भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन पैसा आपकी जेब में नहीं जा रहा है । जो बीच के लोग हैं, जो दलाल हैं, वे पैसा खा जाते हैं, आपको पैसा नहीं मिलता । इसलिए मेरा निवेदन है कि मांग अनुसार पूर्ति की जाए । अनुमान लगाया गया है कि देश में टेलीफोन की मांग बढ़ेगी । 1980-81 में 6 लाख 73 हजार, 1981-82 में 7 लाख 4 हजार, 1982-83 में 7 लाख 8 हजार, 1983-84 में 8 लाख 27 हजार, 1984-85 में 9 लाख 2 हजार, 1985-86 में 10 लाख 5 हजार, 1986-87 में 11 लाख 35 हजार, 1987-88 में 13 लाख 9 हजार, 1988-89 में 14 लाख 39 हजार और 1989-90 में 15 लाख 80 हजार नए टेलीफोस की मांग आएगी । यह रिपोर्ट पी०एम०टी०डायरेक्टरेट इलैक्ट्रोनिक्स स्विचिंग पालिसी पर विभागीय कार्यकारिणी दल की है, इसके अनुरूप हमारा प्रोडक्शन बहुत कम है । हमारी वर्तमान फैक्ट्रियों से भी बहुत कम उत्पादन हो रहा है, जैसा कि देश में

इलेक्ट्रानिक सिस्टम के लिए पालघाट योजना बनाई गई है, उसका उत्पादन भी बहुत कम है। इस संबंध में एक विभागीय रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जैसा कि मैंने अभी बताया है कि 102 लाख नए टेलीफोंस की मांग होगी, इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन जो रिपोर्ट संचार विभाग 1980-81 प्रकाशित हुए है उसमें पेज 37 पर पालघाट योजना के संबंध में विश्लेषण छपा है मैं पढ़कर सुनाता हूं।

"The Phase I of the Palgha Unit to produce 17,500 lines in two shifts working was sanctioned by the Government in 1974 at a capital cost of Rs. 26 lakhs. Except for a few minor works, the Phase I project has been completed as of end 1979-80. The actual expenditure incurred by Palghat Unit during 1979-80 was Rs. 4.10 lakhs."

इसके साथ-साथ पेज -2 में प्रोग्राम में केवल 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। तीन सौ करोड़ रुपए की मांग और प्रावधान कर रहे हैं केवल 60 लाख रुपए का, एक करोड़ भी नहीं है, 300 का एक गुना भी नहीं है। इतनी मांग होने के बावजूद अगर आप इस ओर पूरा ध्यान नहीं देंगे तो जन असंतोष उभरेगा जिसका सामना आप नहीं कर पाएंगे।

सभापति महोदय मुझे विश्वास है कि स्टीफन साहब और पाटिल साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं त्रुटियां हैं जहां पर उनकी उंगली नहीं रखी जा रही है मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि उनको आप देखें, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसे आप कंट्रोल न कर सकें। आपकी कार्य क्षमता पर मुझे पूरा विश्वास है और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इस रुप में काम करेंगे। आजकल रांग नम्बर लगना एक आम बात हो गई है। कभी कभी प्यार भी इससे हो जाता है। इससे शादियां होते हुए भी मैंने देखी हैं। रांग नम्बर, से कुछ लोगों को फायदा भी हो गया है। लेकिन लाखों आदमियों को इसकी वजह से परेशानी भी उठानी पड़ रही है और वे असन्तुष्ट भी हैं। एयर इंडिया ने क्रास बार एक्सचेंज पर एक पोस्टर पब्लिश किया था जिस में लिखा था:

Wrong Number—insert double cross and then delete bar.

डबल क्रास जब लग जाता है तो लड़का फेल हो जाता है फिर चाहे परीक्षा हो या प्यार की बात हो, कोई भी बात हो। हर जगह असफलता ही हाथ लगती है। क्रास बार सिस्टम टेलीफोन में फेल हो गया है। इस वास्ते आपको इलैक्ट्रोनिक सिस्टम की ओर बढ़ना पड़ेगा। जिस स्पीड से आदमी दौड़ना चाहता है जो डिवलपमेंट देश में हो रहा है और जिस तरह से देश हर दशा में प्रगति कर रहा है उसको देखते हुए और उसके अनुरूप हमारा टेलीफोन सिस्टम उसके साथ साथ नहीं चल पा रहा है। रांग नम्बर जो लगता है इसकी ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा। जो मशीनें पुरानी पड़ गई है उनको आपको बदलना पड़ेगा। सुबह से शाम तक ट्रंक काल की मांग करते रहो मिलती ही नहीं है। कोई भरोसा ही नहीं होता है कि कब मिलें। नजदीक की हो या दूर की ट्रंक काल मिलने में दो दो और तीन तीन दिन लग जाते हैं और वेट करना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता था। इससे मानवीय दिनों का अपव्यय न तो होता ही है लेकिन साथ साथ पैसे का भी घाटा होता है।

टेलीफोन विभाग में कुरप्शन बहुत बढ़ गया है। ऊपर की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन जहां मैं रहता हूं वहां एस० डी० ओ० टी० हैं जिन का नाम मुझे नहीं लेना चाहिये भ्रष्ट है। वहां लांग कार्ड डालना है ताला नहीं जाएगा और पैसा दो तो एक दिन में काम हो जाता है। एप्लीकेशन देते रहो तो छः-छः महीने काम नहीं होता है और अगर पैसे दे दो तो एक दिन में हो जाता है। फोन शिफ्ट कराना हो और पैसे दे दो तो एक दिन में नहीं तो छः छः महीने आपका फोन शिफ्ट नहीं किया जाता है। बिना पैसे के कोई कागज इस डिपार्टमेंट में नहीं हिलता। हर जगह कुरप्शन है। मुझ से पूर्व वक्ता, एक माननीय सदस्य ने भी इसका जिक्र किया है। मैं भी पकड़वाने के लिए तैयार हूं। मैं चेलैंज करता हूं कि आप आएं और देखें वहां कुरप्शन है या नहीं है। मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। बिना पैसे के काल तक नहीं लगती है।

रूरल एरियाज के बारे में आपको विशेष विचार करना चाहिये। भारत गांवों का देश है। गांवों में इलैक्ट्रोनिक इक्विपमेंट नहीं है, काम बार इक्विपमेंट नहीं हैं। रेडियो टेलीफोन जैसा कि वायरलैस सैट में होता है इस तरह का प्रयोग अगर आप करें तो इस में आपको कामयाबी मिल सकती है। इसके प्रयोग हुए भी हैं। मेरी स्टेट मिनिस्टर साहब से बात भी हुई है। वह तैयार भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है, इस ओर ध्यान दिया जाएगा। जिन गांवों में पी० सी० ओज की मांग है उनकी इस मांग को भी पूरा किया जाना चाहिये। अधिकांश गांवों में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की भी मांग है। यह जो नया प्रयोग है इसको अगर अमल में लाया जाए तो मैं समझता हूं कि इन सब मांगों की पूर्ति हो सकती है।

टेलीफोन विभाग के कर्मचारी बहुत लापरवाह भी हैं। मेरे यहां आफिस से घर तक ताल एक्सचेंज लगा हुआ है। वह काम ही नहीं करता था। कई बार कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एक दिन मैंने कहा कि काट दें तो दूसरे दिन उन्होंने आकर काट दिया। यह मेरे साथ हुआ है। आम आदमी के साथ कैसे होता होगा। मुझे कहने लगे कि कोई चिंता की बात नहीं और निकाल कर ले कर चले गए। हमारे यहां बहादुरपुर में श्री रामचन्द्र महाजन, सरपंच के यहां फोन लगा है लकिन वह काम ही नहीं करता है। लेकिन कम से कम नम्बर डायल कर लें वह तो दें दें लेकिन यह भी नहीं दे सकते हैं। जो पैसा दे देता है उसका काम बराबर हो जाता है। यह नहीं होना चाहिये। इसका जांच आप अवश्य कराएं।

एक्सचेंज से आठ किलोमीटर के अन्दर आप लाइन देते हैं उसे बढ़ाना चाहिये। बरहानपुर में आर० एम० एस० आफिस खोलने के लिए कई दिनों से मांग चल रही है। आपने स्वीकृति भी दे दी है। खोल भी रहे हैं। परन्तु वहां इसके लिए बिल्डिंग की जो मांग है उसके लिए आप बजट में प्रावधान अवश्य करें। वहां दो सौ टेलीफोन की मांग है। इसके वास्ते एक्सचेंज का एक्सपेंशन किया जाए और नया बोर्ड लगाया जाए। शाहपुर क्षेत्र की आबादी साठ हजार है। उसके आस पास बहुत से गांव हैं जैसे इच्छापुर, चापोरा, दापोरा, घामनगांव, माहद, भावसा, खामनी, नाचेन खेड़ा, मातखेड़ा। वहां लोगों ने टेलीफोन

ले रखे हैं। इस वास्ते शाहपुर में एक एक्सचेंज खोलना बहुत ही आवश्यक है।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां से भोपाल, बम्बई, पटना और दिल्ली के लिये डायरेक्ट लाइनें नहीं मिलती हैं। इसी लिये उनका बढ़ाया जाना आवश्यक है। मेरे संसदीय क्षेत्र के बागली विधान सभा क्षेत्र के मैसून और बिचुकुआं में लोग पी०सी० ओ० की मांग कर रहे हैं। इसलिये वहां पर पी०सी०ओ० खोले जायें। इस के अलावा मेरे क्षेत्र के लोग महाराणा प्रताप, महाराज अगरसेन और छत्रपति शिवाजी की यादगार में विशेष स्टाम्पों की मांग कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि इन वीर पुरुषों की जयन्तियों के अवसर पर विशेष डाक टिकट निकालने की आप व्यवस्था करें।

टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करने वाले अधिकांश इंजीनियर्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स नहीं हैं। लाइनमैन लोग ही प्रोमोशन पाकर इंजीनियर हो गये हैं। जूनियर इंजीनियर, इंजीनियर और डी०टी०ई० जितने हैं इनकी कोई क्वालिफिकेशन्स नहीं हैं, बल्कि प्रामोशन से आ गये हैं जिसके कारण यह लोग सोफिस्टीकेटेड मशीनों को ठीक ढंग से देख भाल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अकाउन्ट सैक्शन में अकाउन्ट सर्विस के लोग नहीं हैं। रिटायर्ड रिंग कमांडर अकाउन्ट सैक्शन का हैड बन कर हमारे यहां रहा है। कैसे यह लोग हिसाब किताब ठीक रख सकते हैं, यह सोचने की बात है।

हमारे देश से बहुत से टैली कम्युनिकेशन्स इंजीनियर्स विदेशों में जा कर काम कर रहे हैं, विशेषकर अफ्रीका में और कनाडा में, और अपने यहां हम दूसरे देशों से इंजीनियर्स बुला रहे हैं। इसको रोका जाना चाहिये। हमारे यहां के नौजवानों को उचित ढंग से प्रशिक्षित कर के उन्हीं को रखना चाहिये।

अभी स्टीफन साहब ने ओवरटाइम बन्द कर दिया है। मैं मानता हूं कि पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। मगर ओवर टाइम बन्द करने के कारण जो वर्कर्स रखे हैं वह ट्रेन्ड नहीं होते हैं जो आपके टेलीफोन्स को ठीक से हैंडिल कर सकें। इस कारण ऐफीशियेंसी गिर रही है थोड़ा-सा पैसा बचाने जा रहे हैं मगर लाखों रुपया एनऐफीशियेंसी की वजह से खर्च हो रहा है। इसलिये मेरी मांग है कि ओवर टाइम को बन्द न किया जाय। और जो ट्रेनिंग लोगों को पैसे के बल पर दी जा रही है उनको विभाग की ओर से हटा कर अलग से प्रशिक्षित करने की व्यवस्था आप कीजिये। क्योंकि बाहर वाले को क्या मालूम कि टेलीफोन पर कच्चा आदमी बैठा है या पक्का आदमी बैठा है। आप वहां पक्के आदमी बैठायें ताकि काल जल्दी में तैयार करे।

आज जो टेलीफोन प्रणाली है वह पर्याप्त नहीं है, हमको अवश्य ही इलेक्ट्रानिक्स की ओर बढ़ना पड़ेगा। स्ट्राउजर सिस्टम फेल हो गया, क्रासबार सिस्टम फेल हो गया। दुनिया के अन्य देश इलेक्ट्रानिक्स पर आ गये हैं, उस ओर हमको भी बढ़ना पड़ेगा। जिस गति से हम लोग बढ़ रहे हैं पालघाट योजना के माध्यम से उससे हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमारे यहां पंटा-कोंटा प्रणाली फेल हो गई है और वह भारतीय मौसम और परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। उदाहरण के लिये भारत में व्यस्तता के घंटों में प्रति टेलीफोन लाइन कोशों का औसत प्रति घन्टा 12 से 15 है, जब कि अमरीका और ब्रिटेन में 2 से 3 है क्योंकि हमारे यहां टेलीफोन उपभोक्ताओं का औसत 0.3 प्रति 100 व्यक्ति है, बम्बई में 4.7 प्रतिशत है, टोकियो में 66 है, न्यूयार्क में 81 है, पैरिस में 106 है, स्टाकहोम में 115 है। इस प्रकार से भारत में टेलीफोनों की संख्या बहुत कम और ऐफीशियेंसी कम होती जा रही है।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय स्टीफन और माननीय विजय एन० पाटिल से

निवेदन करूंगा कि वह अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करें ताकि इस सेवा में और सुधार हो।

श्री डूमर लाल बैठा (अररिया) : सभापति महोदय, संचार मंत्रालय पर काम करने की जवाबदेही बहुत बड़ी है, क्योंकि केन्द्र के दो मंत्रालय, रेल और संचार, ऐसे मंत्रालय हैं, जिनसे देश के आम लोगों का सीधा सम्बन्ध रहता है। शहरों के पढ़े-लिखे लोग सरकार के प्रशासन और कार्य-प्रणाली के बारे में बहुत सी बातों को देख कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, मगर जहां तक देहात का सम्बन्ध है, वे तो इस आधार पर निर्णय करते हैं कि संचार मंत्रालय और रेल मंत्रालय का काम कैसे चलता है।

यह ठीक ही कहा गया है कि देश में संचार मंत्रालय की स्थिति वही है, जो कि शरीर में नसों की है। जिस प्रकार नसें सम्पूर्ण शरीर में रक्त का संचार करती हैं, जिससे शरीर का संचालन ठीक तरह से होता है, उसी प्रकार किसी भी शासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए संचार मंत्रालय को कुशलता से काम करना पड़ता है, और करना चाहिए। इस दृष्टि से संचार मंत्रालय का काम बहुत पीछे रहा है।

इस विषय पर चर्चा करते हुए विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य, श्री मनीराम बागड़ी, ने एक तरफ तो संचार मंत्री की बहुत तारीफ की, उनको बड़ा कर्मठ बताया और उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की, और दूसरी तरफ उन्होंने राय दी कि उनको इस मंत्रालय को छोड़ देना चाहिए। मेरी राय तो ठीक इससे उल्टी है कि जब वह इतने कर्मठ और दक्ष हैं, तो उन्हें इसी मंत्रालय में रह कर उसकी गड़बड़ियों को दूर करना चाहिए। ये गड़बड़ियां आज नहीं आई हैं। ये कई बरसों से चली आ रही हैं और जनता पार्टी के काल में तो पराकाष्ठा पर पहुंची हुई थीं। उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए उन जैसे कर्मठ व्यक्ति का इस मंत्रालय में रहना बहुत जरूरी है

31-3-79 तक एक पोस्ट आफिस औसतन 4,184 की पापुलेशन और 24-46 स्क्वेयर किलोमीटर एरिया को सर्व करता था, जबकि 31-3-80 को एक पोस्ट आफिस 4,001 की पापुलेशन और 23.9 स्क्वेयर किलोमीटर एरिया को सर्व करने लगा। इससे पता चलेगा कि मंत्री महोदय ने करने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये गड़बड़ियां बहुत पुरानी हैं, इसलिए यह कहना बिलकुल गलत है कि इसमें मंत्री महोदय का दोष या कुसूर है और वह इनको दूर नहीं करना चाहते हैं। जमाने से हमारे संचार संयंत्र हैं वे सब पुराने पड़ हुए है। इनको बदलने की आवश्यकता है। बीच बीच में जिस तरह से समय समय पर उस में बदलाव होना चाहिए था वह नहीं हुआ। यह सही है कि आज हमारे यहां जो क्रास बार सिस्टम है उस से काम नहीं चलने वाला है। हम को भी आधुनिक से आधुनिक जो संचार प्रणाली है उसको उपलब्ध कराना होगा।

आज हम पहले पोस्ट आफिस की बात करें। यह जरूर है कि आज हमारी यह स्कीम है कि नार्मली दो हजार की पापुलेशन पर एक पोस्ट आफिस होना चाहिए और जो पिछड़े क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं उन में एक हजार की आबादी पर पोस्ट आफिस होना चाहिए। लेकिन इस को पूरा करने के लिए मंत्री महोदय ने क्या योजना बनाई है? दो हजार की आबादी वाले गांवों में या पिछड़े क्षेत्र में एक हजार की आबादी पर जो पोस्ट आफिस खोलने की बात है उस के लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की है? अभी जो तरीका है वह यह है कि जहां से लोग दरख्वास्त देते हैं जहां के लोग

उस में दिलचस्पी लेते हैं वहां पोस्ट आफिस खुलता है। मगर विभाग की तरफ से भी उस की व्यवस्था होनी चाहिए, इस का सर्वे कराकर जहां पर इसकी जरूरत है वहां पर पोस्ट आफिस खोलने की व्यवस्था विभाग की तरफ से की जानी चाहिए।

टेलीफोन के रख-रखाव के सम्बन्ध में और लोगों ने भी अभी कहा। यह बात सही है कि टेलीफोन की जैसी उपयोगिता है उस को ख्याल में रखते हुए जैसी उस में दक्षता आनी चाहिए, एफिशियेंसी आनी चाहिए वह उस में नहीं है। उसके लिए एक बात तो यह है कि जहां पर उस के अंदर एक ओर इंजीनियरिंग साइड में उस की लाइन को मेन्टेन करने का काम होता है वहां दूसरी ओर जो आपरेटर्स हैं जिन को एक्सचेंज में बैठ कर काम करना पड़ता है इन दोनों में एक अच्छा और वाजिब सहयोग होना चाहिए तभी काम चल सकता है। मैं अपने यहां का उदाहरण बताऊं, मैं अररिया फारबिसगंज से आता हूं जो नेपाल के बोर्डर पर पड़ता है। एक तरफ नेपाल का बार्डर पड़ता है दूसरी तरफ बंगला देश का पड़ता है। हमारा जिला नेपाल और बंगला देश के बार्डर पर है। वहां स्थिति यह है कि जब से हम आए हैं, यानी करीब करीब दो साल हो रहे हैं तब से आज तक टेलीफोन बुक कर कर के थक गए, कोई ट्रंक काल आज तक मैटीरियलाइज नहीं हुई। यह तो वहां के टेलीफोन की हालत है। उस में गड़बड़ी क्या है? मैं जब वहां जाता हूं तो देखता हूं कि एक तरफ आपरेटर्स हैं और दूसरी तरफ आप के इंजीनियरिंग सेक्शन के लोग हैं, दोनों में झगड़ा है और कभी भी तो उन में मार पीट भी हो जाती है। वह क्यों हो जाती है, उसका कारण है। जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा इसमें भ्रष्टाचार की बात है। आपरेटर्स जब काल लगाते हैं व्यापारियों से उन्हें पैसे मिलते हैं। आप जानते हैं कि वह पाटका इलाका है वहां के लोग पाट उत्पादन करते हैं और कलकत्ता की मार्केट में भेजते हैं, तो लाइटनिंग काल की तरह से आपरेटर्स उन की काल लगाते हैं और आर्डिनरी का चार्ज करते हैं, ऊपर ये पैसा खा जाते हैं। जब एक तरफ आपरेटर्स घूस खाते हैं तो इंजीनियरिंग सेक्शन के लोग भी चाहते हैं कि उसका हिस्सा उन को मिले। जब वह नहीं मिलता है तो वे लाइन खराब कर देते हैं। मैं ने मौखिक रूप से इस की शिकायत राज्य मंत्री जी से भी की थी। मैं नहीं जानता कि इस पर क्या कार्यवाही हुई। लेकिन मैं ने एक राय दी कि ऐसा इसलिए होता है कि काफी दिनों तक आप के इंजीनियर, आपरेटर और दूसरे कर्मचारी एक ही जगह पर रहते हैं। उनको दण्ड के रूप में नहीं बल्कि नार्मल व समय आने पर प्रत्येक तीन साल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर देना चाहिए ताकि वहां रह कर जो वेस्टेड इन्टरेस्ट हो जाता है वह न हो सके।

16.00 hrs.

मैं दो तीन बातें कह कर समाप्त कर दूंगा। एक तो यह है कि वहां पर हमारे उस एरिया में फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया इन सब स्थानों पर टेलीफोन को आटोमेटिक करने की आवश्यकता है। उस के कई बार प्रस्ताव आए हैं कि वहां पर आटोमेटाइजेशन किया जाय। मैंने कई बार सवाल भी किए हैं। मगर सरकार पता नहीं क्यों इसमें देर कर रही है वहां पर उसके लिए

मकान उपलब्ध हैं। वहां पर आटोमेटिक सिस्टम न देकर वहां के लिए भेजे गए थे। समूचे संयंत्र को दूसरी जगह भेज दिया है जहां पर मकान नहीं हैं। और जहां मकान हैं वहां पर नहीं देते हैं। मैंने कहा था कि जहां पर आपका भेजा हुआ संयंत्र पड़ा है वहां से उसको आप ऐसी जगह पर भेज दीजिए जहां पर कि मकान है। आपको यह बात देखनी चाहिए कि कहां पर संयंत्र है और कहां पर एकोमोडेशन है। जहां पर एकोमोडेशन है और संयंत्र नहीं है वहां पर आपको उसकी व्यवस्था पहले करनी चाहिए।

मैं माइक्रो-वेव स्टेशन के सम्बन्ध में एक बात खास तौर पर राज्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा जो कि बिहार से आते हैं कि डाल्टनगंज में साल भर से माइक्रो-वेव स्टेशन बनकर पड़ा हुआ है लेकिन आज तक मशीन कमीशन नहीं हो पाई है। मैं उरांव साहब से खास तौर पर कहना चाहता हूं कि वे कृपा करके वहां संयंत्र को जाकर देखें और उसको जल्दी से चालू कराने की व्यवस्था करें।

इसी प्रकार से फारबेसगंज में, मेरी कांस्टीटुएन्सी में, दो साल से माइक्रो-वेव टावर बन रहा है और न मालूम कब जाकर वह पूरा होगा। न मालूम उसमें क्या दिक्कत आ रही है इसलिए आप कृपा करके उसको भी जाकर देखें और जो भी कठिनाई हो उसको दूर करें।

जहां तक आटोमेशन की बात है, अभी रिस्ट्रिक्ट्स की बात तो आप छोड़ दीजिए, जो डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर भी आपने आटोमेशन नहीं किया है। भागलपुर, सहरसा इत्यादि बहुत से डिवीजन हैं जो अभी तक वैसे ही पड़े हुए हैं, आपने आटोमेशन नहीं किया है इसलिए इसकी तरफ भी ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है।

मैंने एक चिट्ठी मंत्री जी को लिखी थी कि जानकी एक्सप्रेस में आर एम एस की व्यवस्था करने की बड़ी डिमान्ड है। डिपार्टमेन्ट ने इसको मंजूर कर लिया लेकिन अब इसमें झगड़ा इस बात का है कि संचार मंत्रालय ने आधा रेल डिब्बा लेने की बात कही है जबकि रेल मंत्रालय आधा डिब्बा नहीं, पूरा डिब्बा देना चाहता है। तो इस आधे और पूरे डिब्बे के चक्कर में आर एम एस की सुविधा जानकी एक्सप्रेस में नहीं हो पा रही। इसलिए मंत्री जी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

जहां तक रांग बिलिंग का सम्बन्ध है, हमारे कई बार लिखने के बावजूद रांग बिलिंग की जाती है। जहां पर ट्रंक काल्स नहीं किए गए वहां ट्रंक काल्स के बिल भी आ जाते हैं और जहां तीन मिनट का ट्रंक काल किया गया हो उसको 6 मिनट कर देने पर भी उतना बिल नहीं बनना चाहिए जितना कि बिल बनकर आ जाता है। जब हम लिखते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं आता है। एक तरफ जो आपकी शिकायत है कि हैवी एरियर्स पड़े हुए हैं उसमें यह भी हो सकता है कि जो आपके बिल्स भेजे गये हों उन पर लोगों ने आब्जेक्शन किया हो। तो इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए कि क्या गड़बड़ी है। पता नहीं बिल बनाने वाले नशा पीकर बैठते हैं या फिर क्या वजह है? इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। जब तक आप इसमें सुधार नहीं करेंगे, लोगों की शिकायतों को दूर करने की तरफ आप सही कदम नहीं उठा सकेंगे।

[श्री डूमर लाल बैठा]

आपने गांव-गांव में पोस्ट आफिस खोल दिए हैं लेकिन वहां पर जो आपने एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल वर्कर रखे हैं वह तीन-तीन साल से पड़े हुए हैं, उनसे आप पूरा काम लेते हैं फिर भी उनको सौ या डेढ़ सौ रुपया एलाउन्स ही मिलता है । आप नये लोगों की नियुक्तियां करते हैं तो उस समय इन लोगों में से जिनमें भी योग्यता है और जिनकी उम्र है उनको प्रेफेन्स देना चाहिए क्योंकि इन लोगों को आपके डिपार्टमेंट में काम करने का एक्सपीरिएन्स है । इसका लाभ उनको मिलना ही चाहिए । मैं समझता हूं इस समय दो लाख एक्सट्रा डिपार्टमेंटल वर्कर्स आपके विभाग में हैं । (व्यवधान) मैं समाप्त ही कर रहा हूं ।

हमारे स्टीफन साहब एक कर्मठ व्यक्ति हैं उनके समय में भी इस विभाग में सुधार नहीं हुआ तब फिर और कब हम आशा कर सकेंगे ? आपकी गांव-गांव में पोस्ट आफिस तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने की जो योजना है उसको आप पूरा कीजिए । इस विभाग में जो गड़बड़ी है उसको दूर करने के लिए आप व्यक्तिगत तौर पर ध्यान देकर वाजिब कदम उठायें । आप को जो संयंत्र बदलने हों, वे बदलिए । गांव-गांव में जो इन्सपैक्टर इन्सपैक्शन करने के लिए जाते हैं, जहां पर गड़बड़ी होती है, पोस्ट-आफिस देखने के लिए जाते हैं, वे वहां जाकर पोलिटिक्स पैदा करते हैं और आपस में मतभेद पैदा करते हैं । गांवों में इस तरह की पोलिटिक्स न पैदा हो, इस ओर भी आपको देखना चाहिए—यह मेरा आपसे निवेदन है ।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि हमारे कर्मठ माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और इस विभाग में और गति लाने की कोशिश करेंगे ।

श्री वीरभद्र सिंह (मंडी) : सभापति महोदय, मैं संचार मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह सौभाग्य की बात है कि इस मंत्रालय का संचालन स्टीफन जी जैसे सुयोग्य मंत्री के हाथ में है और इस में राज्य मंत्री, श्री कार्तिक उरांव तथा उप मंत्री श्री पाटिल जैसे कर्मठ मंत्रियों का भी सहयोग है । मुझे यकीन है कि इस विभाग में जो कमियां हैं, जिनके बारे में अभी माननीय सदस्यों ने कहा है, वे उन कमियों को दूर करने में समर्थ होंगे ।

श्रीमन्, इसमें कोई शक नहीं है कि आजादी के बाद हमारे देश में डाक-तार और टेलीफोन-सेवा में बहुत विस्तार हुआ है । मुल्क के कोने-कोने में डाकखाने खुले हैं, टेलीफोन लगे हैं, मगर जहां पर क्वानटिटेटिव एक्सपैंशन हुआ है, वहां क्वालिटी गिरी है और इन सेवाओं के स्तर में कमियां आई हैं ।

अभी यहां कहा गया कि देश में जहां पर दो हजार की आबादी है, उसके आधार पर डाकखाना खोलने की व्यवस्था है और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां एक हजार की आबादी है वहां भी डाकखाना खोला जाएगा । इसी प्रकार टेलीफोन एक्सचेंज तथा पी० सी० ओ० के लिए भी जो पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्र हैं, उनके जो नार्म्स हैं, उसमें रिलैक्सेशन हुआ है । मगर मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो आपने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और दूरदराज क्षेत्रों के लिए नार्मस बनाए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उसमें रिलैक्सेशन हैं, आपने ज्यादा रियायतें दी हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं । जैसा कि अभी कहा गया कि

जहां पर एक हजार की आबादी होगी, वहां पर डाकखाना खोला जा सकता है। मैं स्टीफन साहब को बताना चाहता हूं कि मेरा चुनाव क्षेत्र सारे हिमाचल प्रदेश का दो-तिहाई हिस्सा है। सारे हिमाचल प्रदेश का रकबा 55 हजार किलोमीटर है और मेरे चुनाव क्षेत्र का रकबा लगभग 33 हजार है और बिखरी हुई आबादी है। एक हजार की आबादी भी आपको आठ-दस मील के दायरे में मिलेगी और जैसी कि आपने एक हजार की आबादी पर डाकखाना खोलने का नार्म्स रखा है, तो इसके आधार पर तो वहां अधिकांश क्षेत्र में एक डाकखाना भी नहीं खुल पायेगा। इसलिए मेरी आप से अर्ज है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, पहाड़ी इलाकों के लिए जो आपने नार्म्स रखे हुए हैं उनको आप रिवाइज करें तथा इस बात को देखें कि जो दूरदराज के इलाके हैं, वहां पर नए डाकखाने खोले जा सकें।

अभी यहां पर टेलीफोन के बारे में भी बात हुई है। कई माननीय सदस्यों ने मांग की कि एटोमैटिक एक्सचेंज लगाइए और कुछ ने कुछ और मांग की, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि यह बड़े दुःख की बात है कि आजादी के 33 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज देश में कई डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स ऐसे हैं जिनमें अभी तक टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है। अभी कुछ समय पहले प्रश्नोत्तर काल में मेरे एक प्रश्न के जवाब में आप ने कहा था कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर्स में टेलीफोन की व्यवस्था जरूर होनी चाहिये। आप देखिये—हिमाचल प्रदेश में लाहोल—स्पीति जिले का हैडक्वार्टर्स कैलांग है, किन्नौर जिले का हैडक्वार्टर—कल्पा है—इन में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से वहां जो दूसरे कैटेगरी स्टेशन्स हैं, तहसील या सब-डिविजनल हैडक्वार्टर्स हैं—जैसे काजा, निचार, पूह मूरंग पांगी और भरमौर आदि—उन में अभी तक टेलीफोन की व्यवस्था नहीं हुई है। मैं आप से दरख्वास्त करना चाहता हूं—इन दूरदराज क्षेत्रों में टेलीफोन की व्यवस्था जल्द से जल्द करें। एक बात मैं यहां पर विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि इन दूरदराज इलाकों में यदि साधा-रण प्रणाली से तारों को खींच कर टेलीफोन लगाये जायेंगे तो वे काम-याब नहीं होंगे। जिस तरह से आप ने लद्दाख में उपग्रह के जरिये व्यवस्था की है आप को उसी प्रकार की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश के लाहोल-स्पीति, किन्नौर तथा चम्बा क्षेत्र के पांगी और भरमौर इलाकों के लिये भी करनी होगी।

अभी टेलीफोन विभाग की काफी आलोचना हुई है। मैं समझता हूं कि काफी हद तक वह सही भी है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं—डाकतार विभाग हमारे देश के उन विभागों में से है जिस का जनता से सीधा सम्बन्ध रोज का सम्बन्ध रहता है। जहां हम इस विभाग की कमियों की आलोचना करते हैं वहां इस बात को भी न भूलें कि यह प्रतिदिन बहुत अच्छा काम भी करता है। देश में रोज करोड़ों चिट्ठियां भेजी जाती हैं जो अधिकांश अपने डेस्टीनेशन पर पहुंचती हैं। लोग लाखों टेलीफोन रोज करते हैं, लाखों की संख्या में तार भेजे जाते हैं उन में से अधिकांश ठीक समय पर अपने डेस्टीनेशन्ज पर पहुंचते हैं। यह ठीक है कि जो अच्छा काम होता है उस की तरफ ध्यान नहीं जाता, लेकिन अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उस को ज्यादा उछाला जाता है। इस लिये जहां हम उस की आलोचना करें

[श्री वीरभद्र सिंह]

वहां इस बात का भी ध्यान रखें कि इस प्रकार की आलोचना न करें जिससे विभाग के कर्मचारियों का मनोबल गिर जाये। अगर हम रोज यह कहते रहे कि ये अच्छा काम नहीं कर सकते, इन में अच्छा काम करने की क्षमता नहीं है तो वह वक्त भी आ सकता है जब इनके अंदर अपने सुधार की ख्वाहिश ही मर जायेगी । वे कहेंगे कि हम चाहे कितना ही अच्छा काम करें हमारे काम की कद्र नहीं होती है इस लिये अपने को क्या सुधारें । इस लिये जहां आलोचना करनी चाहिए वहां यह विभाग जो अच्छे काम करता है उस की प्रशंसा भी होनी चाहिये ।

हमारे देश के रकबे को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए यह विभाग कई कमियों के होते हुए भी देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहा है, यह अच्छा काम कर रहा है। इसके लिये सारा विभाग और मंत्री जी प्रशंसा के पात्र हैं।

जहां तक टेलीफोन एक्सचेंजेज का सवाल है बहुत से सदस्यों ने क्रास-बार एक्सचेन्जेज के बारे में बहुत आलोचना की है। इस के बारे में काफी लोगों के दिलों में थोड़ी मिसअण्डर-स्टेण्डिंग है । क्रास-बार सिस्टम अपने आप में बुरा सिस्टम नहीं है, यूरोप के कई मुल्कों में क्रास-बार सिस्टम काम कर रहा है और बड़ा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन हमारे देश में यहां कि जलवायु को ध्यान में रखते हुए, यहां की वर्किंग कण्डीशन्ज को ध्यान में रखते हुए, हमारी एक्सचेंजों पर जो भार है उस को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे या सफल सिद्ध नहीं हुए हैं। इस सम्बन्ध में दो-तीन बातों की तरफ विभाग का ध्यान जाना चाहिए— जितनी भी पुरानी मशीनरी और इक्विपमेन्टस हैं उनको रिप्लेस करने के लिये कदम उठाये जायें। दूसरे देश के अन्दर जहां नये एक्सचेन्ज बनाये जाएं उनमें पुरानी टेक्नालाजी के बजाय नई टेक्नालाजी का प्रयोग किया जाये, जैसे इलैक्ट्रोनिक और दूसरे सिस्टम हैं— वे ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। उनके आधार पर इनको बनाया जाये ।

अन्त में मैं एक-दो बातें अपने-क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष में डाक-तार और दूसरी सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ है। इसके लिये हम विभाग के बहुत आभारी हैं । मगर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश में डाक-तार विभाग का एक सर्किल बनाने का निर्णय हुआ था उसके लिए यहां से मंजूरी भी हो गयी थी । लेकिन उनको मंजूर हुए भी कई वर्ष हो गये हैं, उसको खोलने के बारे में अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने कई लाख रुपये का एक भवन खरीद कर इसके लिए देने की पेशकश की थी लेकिन उसमें किराये का झगड़ा पैदा हुआ । हिमाचल प्रदेश सरकार कहती थी कि हम यह भवन देंगे, आप इसका किराया दो लेकिन पी० एण्ड टी० डिपार्टमेन्ट बिना किराये पर वह भवन देने के लिए कहता था। उसके बाद यह सुझाव दिया गया कि यह सर्किल जोगिन्द्र नगर में खोला जाए। लेकिन वहां के बारे में विभाग ने कहा कि वह कोई बड़ा शहर नहीं है, वहां पढ़ाई-लिखाई आदि की सुविधाएं नहीं हैं। मैं आप से कहना चाहता

हूं कि इस निर्णय को इम्प्लीमेंट किया जाए और इस सर्किल को हिमाचल प्रदेश में खोला जाए। अगर शिमला या जोगिन्द्र नगर में यह नहीं खोला जा सकता है तो वहां पर एक सब से उपयुक्त स्थान सुन्दरनगर है, वहां पर इसको खोला जाए। इससे हिमाचल प्रदेश को फायदा होने वाला है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि डाक तार विभाग के जो कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में काम करते हैं उनकी कुछ कठिनाइयां हैं। उनको वहां बर्फ में, तूफान में डाक तार की सेवाएं बनाये रखना पड़ता है और उन्होंने उनको बराबर बनाये रखा है। इसके लिये मैं उनको मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी जो कुछ कठिनाइयां हैं जैसे कि उसका कम्पेनसेटरी भत्ता है वह उन्हें उतना नहीं मिलता है जितना कि हिमाचल प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को मिलता है। उनकी मांग है कि उन्हें भी यह भत्ता उसी दर पर मिले जिस दर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलता है। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करेंगे।

एक मेरी मांग यह है कि हिमाचल प्रदेश में आपके कई जगह पर वायरलैस स्टेशंस खुले हुए हैं। मैं यह देखता हूं कि पी० एण्ड टी० के जो वायरलैस स्टेशंस हैं उनका मेन करने वाले कर्मचारी वहां नहीं पहुंच पाते क्योंकि आप दिल्ली से या अम्बाला से कर्मचारियों को ट्रांसफर करके वहां भेजते हैं और उन्हें लाहौल-स्पीति जैसे बर्फीले क्षेत्रों में सर्दियों में रहना पड़ता है। मेरा आपको सुझाव है कि आप इन वायरलैस स्टेशन्स को मेन करने के लिए तथा अन्य वहां के स्थानीय लोगों को या वहां के एक्स सर्विसमैन को प्रशिक्षण देकर डाकतार व टेलीफोन सेवाओं के लिए वहां पर लगाइये। आप उनको सभी फेसिलिटीज और ट्रेनिंग देकर वहां पर नियुक्त करें जिससे कि आपको उन स्टेशन को मेन करने में जो डिफिकल्टी हो रही है वह दूर हो सके।

अन्त में एक बात कहना चाहता हूं कि आप बहुत से महापुरुषों की स्टाम्प निकालते हैं। अभी अखबारों में पढ़ने को मिला कि चन्द्र शेखर आजाद जो कि एक क्रांतिकारी हुए हैं उनकी स्टाम्प निकालने की मांग की गयी थी लेकिन अखबार के मुताबिक विभाग ने उस मांग को नामंजूर कर दिया। यह बड़े दुःख की बात है और बड़ी हैरानी की बात है। मैं नहीं जानता कि कहां तक यह बात सच है। अगर यह बात सच है तो ऐसा नहीं होना चाहिए और चन्द्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी तथा अन्य क्रांतिकारियों का हमें पूरा सम्मान करना चाहिए और उनके सम्मान में डाक टिकट निकालने चाहिए।

इतना कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : चेयरमैन साहब,

भला क्या कर सकें इलाज मर्जे नातवानी का।

पकड़ते हैं बाजू तो वहां शाने उतरते हैं।।

अगर हम अपने मिनिस्टर साहब से बात करते हैं तो दिल खुश हो जाता है। लेकिन जब इनके महकमे की तरफ, इनके काम की तरफ देखते हैं तो दिल बुझ जाता है। जो टेलीफोन एक्सचेंज पहले हैं, वे तो सही काम नहीं कर रहे हैं जो नए लगेंगे, उनकी क्या हालत होगी? हमारे यहां एक शहर सनाम है पंजाब

[श्री सुन्दर सिंह]

में, यह तहसील है; यहां पर एस० टी० डी० लगाने के लिए मैंने लिखा, आपने लगा दिया, लेकिन बाद में बन्द कर दिया । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बन्द क्यों किया गया ? इसी तरह से एक गांव है पंजाब में, जिसका नाम बंबियाल है, यह गुरुदास पुर जिले में है, यहां पर डाकखाना नहीं है, वहां पर 500 गांवों में एक ही डाकखाना है । इसलिए मेरा निवेदन है कि विहां पर डाकखाना लगाया जाए ।

अभी मेरे से पहले एक वक्ता ने काफी नुक्ताचीनी इस विभाग के बारे में की और बहुत से प्वाइंट रेज किए, इतने तो मिनिस्टर साहब को भी पता नहीं होंगे । मैं तो कहता हूं कि इसे मिनिस्टर बना देना चाहिए । उन्होंने बड़े अच्छे सुझाव भी दिए हैं । स्टीफन साहब बड़े लायक आदमी हैं और कहते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं है, बड़ा अच्छा काम चल रहा है । अच्छा काम ऐसा चल रहा है कि टेलीफोन बुक करा दीजिए और आराम से हफ्ते दो हफ्ते में जाकर सुन लीजिए । कोई परेशानी वाली बात नहीं है । बड़ी अच्छी हालत है । मैं तो कहता हूं कि ये महकमा इनके बस का नहीं है । आप एक हफ्ते के लिए यह महकमा हमें दे दें, मैं ठीक कर के दिखा दूंगा । हमें टेलीफोन करते हैं, वहां पर लड़कियां बैठी होती हैं । लड़कियों को कुछ कह भी नहीं सकते । वे कहती हैं कि चौधरी साहब, आपने टेलीफोन बुक कराया था, दो दिन हो गए हैं, इससे अच्छा तो आप लैटर डाल देते तो जसका जवाब आ जाता । यह हालत है इस विभाग की । उस विभाग को पैसा बहुत कम दिया गया है इतना इंपोर्टेंट विभाग है इसे तो करोड़ों रुपया दिया जाना चाहिए, जबकि एक करोड़ रुपया भी आपने नहीं दिया ।

सभापति महोदय, आज हर आदमी टेलीफोन मांगता है, लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं आप मेम्बर बन गए हैं, हमें टेलीफोन ही दिलवा दीजिए । हम लिख देते हैं। वहां से जवाब आता है कि हम सोच रहे हैं । मैं कहता हूं कि पहले जो टेलीफोन हैं वे ही ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो नए लगवाकर क्या करेंगे ? इसलिए मैं कहता हूं कि यह विभाग बड़ा अच्छा काम कर रहा है, किसी प्रकार की नुक्ताचीनी करने की जरुरत नहीं है ।

MR. CHAIRMAN: The Minister has taken note of all these points.

श्री सुन्दर सिंह : जहां तक ड्यूटी का सवाल है, इस विभाग में कोई आदमी टाइम से ड्यूटी नहीं करता ।

"The right performance of duty in any station of life, without attachment to results, leads to the highest realization of perfection of the soul." This is what Swami Vivekananda said.

जहां तक रिश्वत का सवाल है, रिश्वत कहां नहीं है । मेरा तो कहना है कि इसे रेगुलराइज कर दिया जाए । एम० पी० के पास जाने की क्या जरुरत है, अफसर के पास जाओ और रिश्वत देकर काम करवा लो । कोई चिंता की बात नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इन अफसरों को थोड़ा खींचने की जरुरत है ताकि ये ठीक काम करें । इतने मिनिस्टर हैं, लेकिन काम सिर्फ 1-2 आदमी ही करते हैं, बाकी सब खाली रहते हैं । इनको क्या टेलीफोन का महकमा दे रखा है, मैं क्या कह रहा हूं यह इनकी समझ में ही नहीं आ रहा है । मैं कहता हूं कि जगन्नाथ जी को मिनिस्टर बना दो, किसी पंजाबी को दे दें, एक मिनट में ठीक कर देंगे, हम भी इनके साथ काम करेंगे । इस महकमे को

पैसे की जरूरत है । इनको पैसा ज्यादा मिलना चाहिये । आपने एक करोड़ भी नहीं दिया है । ये बेचारे क्या करेंगे । इनकी भी मजबूरी है ।

महकमे को इनको ठीक करना चाहिये । लोगों में इस वजह से परेशानी बहुत ज्यादा है । इतना ही मुझे कहना है ।

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI C. M. STEPHEN): Mr. Chairman, Sir, I am deeply indebted to the House, to the Minister of Parliamentary Affairs and the Speaker for having arranged this, after a long number of years, that a discussion on this Ministry comes on the Floor of the House. Whenever a criticism arises on the functioning of this Ministry, I feel fairly happy because a message goes out from here to lakhs and lakhs of the workers who are working in all parts of the country, a message to the effect that the representatives of the people are not happy about the way things are going on. There could be nothing more competent nor more efficient nor more powerful than this message to enthuse them and put them on the toes. Therefore, I was happy that this debate came up. I had asked all my circle chiefs to be available in Delhi and they are here in the Official Gallery hearing the discussion that was going on. I wanted them to hear straight from the horses' mouth as to how the Department is judged by the people and their representatives. Therefore, I had arranged it and they are all here. They had been listening to all the criticisms that had been going on. But I am slightly disappointed in the sense that the criticism that came up was not as bitter or as acid or as hostile as I expected it to be or to be frank I wanted it to be. It may be that out of their personal consideration for me, they had put it in a very mild manner. I wanted it to be a little more sharp because I think the overall going on deserves a little more of grubbing, a little more of drilling. This is a democratic process and I feel, considering the importance of this Ministry, importance much more than many people visualised in the matter of development of the country, in the matter of keeping the country together, in the matter of enabling our people to communicate to one another, a very crucial role that this Ministry is playing. I would feel that hereafter a debate on this must be a must when the budget discussion takes place.

I was also heartened to hear an expression of opinion particularly from my friends from the opposition that there should be a separate budget for this Ministry. I reserve my comments. I shall not make any comment about it.

SHRI R. K. MHALGI: Why have you raised it?

SHRI C. M. STEPHEN: That is all right. But that shows the anxiety of the members to get a full picture of what exactly is happening here, that if a document is placed before them, they will get a complete picture of the developments that are taking place. We are on the door-step of uninconceivably large expansion and development; we are on the threshold sector-wise and area-wise to be be and this decade will be a decade of break through. 1981-85 will be a period of a turn-over to a new leaf and it will be a thrust forward. Therefore, this is necessary that the Parliament knows and every Member of Parliament knows what is exactly happening in the Ministry in its multi-faceted aspects.

Now, I have been concentrating attention on the different parts of the Ministry as far as I could, in the expectation that my effort will get felt. It is getting felt. I have got that satisfaction. But the Ministry is such that, however, much you may improve, there will still be left something unsatisfying and inviting criticism. That is the position in this Ministry.

[Shri C. M. Stephen]

The Postal Department's function has been criticised. The fact remains that the Indian Postal system is adjudged best in the world. Nobody has controverted it. Our functioning is the very best. I do not think that there is any relaxation at all. But, everybody who gets a letter slightly late, comes to his own conclusion. We do not look at the envelope. We take out the letter. We look at the date, and we see the letter. Immediately, we come to a conclusion.

Every day three crores of postal articles are being lifted from one end of the country to another and are being distributed through, about 1,37,000 Post Offices, going through different areas; thousands of sorters are doing the work of sorting. When crores of letters are being sorted by a human agency, it is possible that a letter meant for Chandigarh may fall into the docket for Cochin. It is possible. These things do happen. It happens for a few letters. I will just give you an example. We have got 515 Dead Letter Offices. Do you know, the number of letters that come to the Dead Letter Offices? Two hundred and forty-eight lakhs of letters come to those DLOs every Year! Out of that 75 per cent are found out. They are either returned to the sender or the addressee is found out from the inside and the letter is forwarded to him. But the point is this—forget about the sorter—the man who writes the letter, he writes it in such a manner that the letter lands in the Dead Letter Office. After going through it or inquiring it lands up there. And the number is to the tune of 80,000 per day. That is the number of letters going on like that. And out of them about 20 per cent are registered letters. That means, through the registered letters people who pay the money are that type of letters come and land there. So, there is a human error. That is what I am saying. If with a man who writes a letter an error can take place, the sorter who is dealing with thousands of letters, and who is just putting them in different dockets commits an error, the whole letter lands at some other place.

Many Members spoke about the memorandum that was presented to the Prime Minister when she had visited Bhubaneswar. Mr. Rath who presented the memorandum is a very respected person; very well known to the Postal Department, held in very good esteem he is respected. Therefore, he should not be questioned. Out of his conscientiousness he gave it. Immediately after I saw this I asked for a report and asked Shri Rath to hand over all the letters that he had. I am just citing an example about the measure of our judgment. I am just pointing out. He handed over some letters. There was a letter from the President of India. It was dated 26-2-81. It was posted in Delhi on the 2nd. It reached Bhubaneswar on the 4th. We have got it from the stamp. It is about the letter which was dated the 26th. But it was a posted only on the 2nd. And it reached Bhubaneswar on the 4th.

16.34 hrs.

[**Mr. Deputy-Speaker** in the Chair]

The next is another letter of the Servants of India Society. That I will take up later.

There is one from the People's Society, from New Delhi, dated the 26th, posted on 27th of February. It reached Bhubaneswar on the 2nd. In the meanwhile, there is a Sunday. On a Sunday the Department does not operate at all. Therefore, practically, within three days it reached Bhubaneswar. The next one is from the Servants of the Peoples Society, dated 28-2, posted on 2nd and reached 5th. The third one is dated 14th, posted on 16th and reached Bhubaneswar on 18th. Another letter from Bhubaneswar dated 25th, posted on 4th and delivered on 5th. Another letter posted on 2nd and reached

Bhubaneswar on 4th. Another posted from Ganjam on 2nd and reached Bhubaneswar on 4th. There is one letter which took 21 days. But that was not a letter but a book post. This is a thing which everybody must understand. Book post never goes by air. It is a 'B' class mail. It goes only by train and it goes to Bombay. There is another sorting. It will have to go to different stations. And that happened to be December. Month of December is the greeting card period. Huge mail comes up. Therefore, these things that come by book post just get delayed. It just takes time. This is a lesson I have learnt. This year, for the season time, special arrangements will be made. At that time, there was a strike in Bombay. There was something in Bhubaneswar. All these things caught this up. But the point is that out of all these letters, for which the Postal Department was criticised, except one, went across and reached the other end within two or three days. If you take the date of the letter, then it is delayed. If you take the date of posting, then it came on time. This is just to point out that our Postal Department is not that bad as many of us think it. It is functioning fairly all right thinking all the huge load that we are carrying, all by human agency and not a single area is covered by machine. Hand and precision go on. We are not masters of the transmission system. We have got to depend on the railway, buses, planes. If one plane is delayed and another is not caught, I am caught up. If the plane is delayed and the bus is not caught, I am caught up. These areas also are there. In spite of all this, in the huge mail, from one end of the country to the other, letter travels. We have got the system of sending test letters. Thousands of letters are being sent by officers and letters come back. We make an assessment. My assessment is fairly satisfactory.

Rather than the test letters, I have introduced another system. We have got large number of offices. Thousands of letters are coming. We are collecting all the postal covers together. We decide how much time one letter is taking from one station to another. I must say that the result is satisfactory. But not that it cannot be improved. However, much you may improve, there is a human error. There is a slip between the cup and the lip. Something can happen somewhere. This is the point I wanted to mention. I must express my admiration for the way the lower paid employee in this country is working in the Postal Department and is carrying this huge load across. This is a matter which must be acknowledged.

MR. DEPUTY-SPEAKER: When you send test letters next time, send them at the addresses of the Members of Parliament also.

SHRI C. M. STEPHEN: I am not sure whether I will get them back.

About telephones, I am fairly satisfied that, however, much I may improve it, I am not going to get a word of congratulation because still there will remain unsatisfactory areas. It so happened that last week in the library I came across a paper published from London. It is 'Observer'. London is supposed to be having a good tele-communication system. People tell me that their telephone system is excellent; your telephone system is backward, look at their telephone system. There is an article on that. The article is 'The ring of no confidence.' "It takes ages to get a telephone, then it drives you mad once you have got one." It says.:

> "An estimated 40,000 in the London area alone are waiting to have a phone connected at all, partly due to shortage of line plant, partly to lack of exchange capacity.

They are an advanced country. Still they have the shortage of line equipment. Then it is said:

> "But the pubic outcry at the prospect of change gives some idea of how close the public feels to

[Shri C. M. Stephen]

those familiar red booths. 'If they made the bloody things work instead of painting them, it would be more to the point,' is the general comment."

About the working of the telephones this is the general comment. Again it says:

"But people seem prepared to wait so that they too can suffer. The advertisements tend to suggest that, even if there is a line available, connection will take about two to three weeks."

Here also the complaint is tne same. After the OB is issued, it takes 3 to 4 weeks. That is the complaint here also. There also the same is the complaint, the language is universal. It further says:

"....in London at least, it is often 18 months to two years before the instrument can take its place in the range of tortures.'

"And there are very special tortures to come, too; on average, only 63.7 per cent of calls are successful, even according to the Post Office."

That is to say, for every 100 calls you ring, only 63 per cent comes through. All the others fail. 37 per cent of the calls fail in the great city of London. This is the position. The comment is:

"But that successful connection, after all, may well be the wrong person on the wrong number and should not count as a victory for the telephone service."

The same thing is here—wrong number, wrong person landing up, and it is the same that way.

It is stated:

"We should really use 'wrong' as the past tense of 'ring' given the telephone service we have. But other people's telephone conversation, across a crowded line, is much more fascinating than our own. On an instrument which in our everyday life is perhaps the one and only source of hope that anything could happen, mundane mutterings between two strangers can promise intrigue, adventure, passion."

This is the condition of the London Telephones given here. It has got to be conceded that telephone is an advanced system. But there is that long waiting.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think the British have not left that legacy here.

SHRI C. M. STEPHEN: We have improved very much. We have certainly gone far ahead of that legacy. But this is the position everywhere.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): We need not expect any improvement in the telephone. This seems to be the ideal before you.

SHRI C. M. STEPHEN: No. This is not the ideal. However, ideal it can be, there is a shortfall. That is what I am saying. In Japan which is admittedly the very best, the maturing call is 70 per cent. It is their own record. There is this mechanical thing, messages crowding in and everything is not getting through. It is the very best in the whole world. Their total effective call percentage is 70 to 75 per cent. London is the next where it is 67 per cent. Ours comes to about 52 to 53 per cent. We can certainly make a headway. I am only saying that this is the position everywhere. I am not saying this as an excuse. It can be improved. But I should say that our equipment has got its backwardness and technological deficiencies. It is a conglomerate of different systems which are operating here. Some of the exchanges are aged, which have got to be replaced. All these things are there. Different exchanges are coming in, the difficul-

ties are there. In cities like Calcutta the cable is being cut. Here the cable is cut into because we are developing. Therefore, in a little available space, every type of cable system is struggling to get its own space and in the process getting it damaged. All these things are there. With all that, we can definitely improve. Service can definitely improve if all the employees in the Department apply themselves completely and conclusively to the task. I can point out that there is a difference if you go to South. In the southern belt of India the service is fairly good. In certain areas service is not that good. I am only saying, 'in certain areas it is not that good—I am not saying North, East, West and all that. In certain areas it is not that good, which shows that the system is the same. But the service and quality differs. It depends upon the way the thing are managed there, the supervisory efficiency that is exerted there. My own analysis is that it is not the workers who are to be blamed, but it is the supervisory efficiency that has got to be blamed. I am trying to gear it up to a great extent.

Along with this there was a complaint about the telegram which reached Bhuvneshwar after four days. I made an investigation into it and certain facts emerged—carelessness in the manner it was being dealt with; upto Bhavneshwar there was on a particular day about 280 telegrams of 36 hours duration had piled up without anybody looking into it. It is total collapse of the supervisory alertness. Therefore, we had to take action. Certain supervisory persons have been suspended. Action has been taken. I would rather go ahead taking action against those persons who are not exercising their supervisory function rather than against the worker who is down at the lower level. We will go ahead with it to see that proper supervision is exercised. This is a point I am trying to put into their concept.

Certain criticism were made. With all these defects I must say there are 22 crores of trunk connections which are being put through every year. We collect about Rs. 125 crores on the trunk connections that we are giving. Local connections that we are putting up come to 720 crores. Local connections are being put through per day—two crores—in the whole system. Two crores of units are passing through. Thi is the result of that system that we have—it is working to some extent. This much out-turn it is taking up. International ten lakhs connections are being put through.

About the bill complaints I may say that about two crores of bills are being issued. Against that metre complaint comes to 70,000 only. Two crores bills cover about Rs. 500 crores. As against that this is the metre complaint—that we are getting, complaint of this bill and that bill and all that comes to 1.5 lakhs. But the metre excess complaint is only 70,000 and in the year 1980-81 it is not that we are callous; every complaint is examined—in 1980-81 I paid back Rs. 1 crores as rebate admitting that there was an excess. Excess, wherever there is, is being given. Rs. 1 crore has been given back as rebate. It is not as if we are remaining as dead wood, not considering difficulties and all that.

As I said the working people have to gear themselves up, certain actions are being taken. We have got two federations. The meetings of the executives of the two federations, the working committees, were called Entire Board and myself sat with them. I told them and they accepted that we have got a sacred duty of commitment to the people. We may have our own difficulties, differenecs, that is our internal family problem. It must be tackled by a collective exercise within the family. But for that we shall not hold the people at ransom. We shall not hold them as hostages. I was very blunt. I was clear with them. If a demand is

[SHRI C. M. STEPHEN]

coming up backed up with an unauthorised cat-call strike. I told the federation friends that I will not look at the demand at all. But if even an unreasonable demand comes on as dialogue basis across, I am prepared to move in, even if it is unreasonable, to some extent to meet the demand, because this is a Department where the strategy of holding people to ransom cannot be resorted to. It is not collective bargaining with me, but it is collective bargaining with the people at large. The poor man sitting in the far away village should not be held at ransom. I was extremely happy to know that the response of both the federations was extremely positive and they assured me that "We are for workers. We are not for shirkers; we will not support any go slow, any work to rule, this sort of business." Anything coming up, I told them, if on anything their National Committee took a decision to call on strike, I would treat it as a trade union action and we would sit across. But cat-call strike, go-slow, without national leaders' permission, if it comes, up, we have to face it because it is a child without a father without a parent. It just starts and it cannot be tolerated. This is the position we have taken. Therefore, I shall make an exercise with them. They have promised me cooperation and they have started writing in their journals, exhorting workers to give better efficiency. I am extremely happy to say, they have got union journals and they have started writing in them about that. I must say on the floor of the House that I will respond to them to the measure in which they are extending their cooperation.

I cannot say that my worker is the best paid. I cannot say that everything that should be done is being done. It deserves better treatment and how it can be done is a matter which concerns me. This must be a satisfaction to the workers that I own that their difficulties have got to be attended to. The housing problem and everything is being considered. I have called the Circle Chiefs. They are sitting and the ideas are being put across.

Certain arrangements are being brought about in the exchanges. You call somebody and you do not get it. These are the measures I have directed them to take. I propose to strengthen the complaints cell. A complaint coming in writing to me is a warning signal. It is not for merely to rectify that measure. It must be taken as a warning signal An inquiry will have to be made, to find out what exactly is the difficulty and, in the process, wrong-doing will have to be unearthed in this vast area and, therefore, that sort of a complaint is a precious thing which gives me a clue to get to the rotten place and make the rectification. At the supervisory level, I have said that this is an area where I am trying to gear them up.

Bad practice in trunk booking was mentioned here, that certain people who pay money get a prior deal and the other man is overlooked. I have now directed that we give a docket to them; one by one, the number is there. They generally mark it, No. 100th—line out of order, and jump over to the next man and give him a connection. I have directed them, "If you want to jump over to the other man, you cannot keep the card. You have to hand it over to the Supervisor." That will go to the Supervisor. Separate three or four spare boards will have to be set up. Higher type of persons will be there and they will try again to see whether the line is out of order. They will give a second trial on another board so that this sort of thing can be detected. This is what we are attempting to do.

Then, if no-fault report is given—generally, we find that about 50 per cent of the complaints are that the subscribers are told, "Telephone is out of order"—we immediately again dial up and if we find, there is no fault, they generally remain satisfied with

that. It can happen that the report is not a correct report. The subscriber will be feeling, "I have lodged a complaint" and we will be feeling there is no fault at all. There is a communication gap. This communication gap must be filled up. Therefore, it has been suggested that there must be a second check up done for that.

For repeat complaints, if there are more than three repeat complaints, coming on a particular telephone, then a special attention will have to be paid to that and we will have to inquire at a higher level as to what is happening about it. Observer units have been set up in the major exchanges and somebody will be watching out what is going on in the exchange and will be detected. If anybody is caught passing an unauthorised call, very strong action will be taken and has been ordered to be taken.

These are some of the measures we are taking, to find a way to check corruption that has been mentioned about. Only about 3 or 4 days back, I had called a meeting of the Vigilance Officers on an all-India level in my Department. The Prime Minister had given a call, when she inaugurated the CBI Conference, that every Department must tune up Vigilance section. We call them vigilance departments. I am proposing to plant in my Department a cell with an investigative thrust so that this aspect can be gone into. The vigilance deparmanent is only for the purpose of taking disciplinary action and all that. It must have this sort of a thrust. This is the way in which we are proceeding.

Transfers are not being done was one thing that was mentioned here. I have only to report that rotational transfers are absolutely necessary. As far as my Department is concerned, I pleaded with the Cabinet that I may be permitted to do that and I have got the permission. These rotational transfers will take place rather than somebody remaining there, striking root and developing vested interest. Therefore, they will have to be uprooted and put in a convenient place somewhere else so that everybody can get the benefit of every employee throughout the country in different areas. This arrangement is also being done. There will be no doubt about it.

A mention was made about the amendment to the Act. I made an exercise to see whether amendment is necessary at all. Some amendment is necessary. The exercise is almost complete. I think the matter is with Mr. Shiv Shankar. I will get it back. I propose to bring the amended Bill by the next session. (*Interruptions*). That is what I am expecting to be able to do. It is an exercise. It takes its own time.

A mention was made about OTA, the most important matter. It is said that I banned OTA, that I prohibited OTA. I said that OTA is jumping up and that there must be control on it. From just Rs. 9 crores, it jumped up to Rs. 26 crores. It cannot go on like this and, therefore, an exercise was made. I must own that I have been defeated in this struggle. The result is that this year's OTA comes to about Rs. 28 crores as against Rs. 27 crores last year. But, even then, nobody need be flabergasted about it because it is only 5 per cent of the total wage bill. This is only about 5 to 6 per cent of the total wage bill of about Rs. 500 crores. According to me, the reason for a major part of the malfunctioning of the department is the accumulation of vacancies. Over the years, thousands of posts remain vacant and unfilled. In a country where unemployment is rampant, I do not find any justification for not filling up these posts. Because of these vacancies, Overtime had to be put in. And all sorts of evils follow from that. It has been ordered that these vacancies must be filled up. 31st March was the final date before which these posts had to be completely filled up. Recruitment has almost been completed according to the target. But that does

not mean that people go on to the their seats because training period has to be gone through. It may be for 5, 6 or 12 months. This training has to be there.

I have also started a method of building up a Pool. Not only recruitment will take place for the last year but for the current year also, recruitment will take place in anticipation, taking into account the possible requirement for the coming year, and the recruitment will take place for that. They will be sent for training. They will be kept fully equipped. They will not get full job. That is all. Whenever there is absenteeism, we will just put them to do short duties of work. And whenever there are vacancies, they will be immediately taken in to fill up the vacancies and, therefore, I think these posts remaining vacant will be a thing of the past. It will not happen hereafter because Pool system will take care of it. The moment there is a vacancy, this can be filled up and that will go a long way to meet the requirements. This is what I have to say.

As regards rural telephone system, it is one of our great challanges. Today, if you take the core or the rural area, only 5 per cent of the whole telephone system has gone up to the core or the rural area. If you take the peripheral quasi-urban area also, about 15 per cent of the total telephone system had gone there. 85 per cent are in the remaining urban area. For the time, we have necessarily got to expand the rural area because we are setting up our industries there.

The developmnt activities are going on in the hill areas. It has to be supported by tele-communication system. But, it is not as simple as we think because it means lot of expenditure and the return will be very low. We cannot expend that way with the return position very much low. Then the total working of the Department will be very very badly affected. How exactly it should be done is a matter with which we are concerned. On the one hand, we have got that problem. On the other hand, we have got extra departmental officers' problem. I will take up that matter. I am now thinking why not the small exchanges and the extra-departmental offices and the rural offices, the post offices, together be combined so that together they will be able to make themselves viable and they can work for more than 2 or 3 hours or even full time.

17.00 hrs.

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Interesting experiments are being made in Andhra.

SHRI C. M. STEPHEN: In Andhra, many experiments are being made—many experiments in the tele-communication field. This is something we are thinking about. We are expanding in a very big way in this area. Rural tele-communication system has got to be developed. This is an obligation which is certainly on us.

Mention was made by Mr. Mhalgi about postcard and all that. I do not know whether he realises what exactly I am losing by this postcard business...

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Before you go to postcard, may I ask you a question with reference to expansion of tele-communication system in the rural areas? Can you prescribe a minimum in every taluk? I had asked a question, an Unstarred Question, the other day: 'whether it is a fact that in Poladpur of Raigarh district there is only one PCO, where there are 75 villages, and if so, whether this is adequate' and the answer given is 'yes'. I do not know whether this is the maximum you can do or you can prescribe some minimum. Where there are 75 villages, at least there should be five or 10 PCOs. What is your policy with reference to expansion in the rural areas in respect of postal and tele-communication sys-

tem? If you can give that policy on the floor of the House, I will be much obliged because, in the last seven years, we have not debated on this.

SHRI C. M. STEPHEN: My policy is to be very flexible.

AN HON. MEMBER: This is an evasive reply.

SHRI C. M. STEPHEN: It is not an evasive reply. Certain norms were prescribed there. I am having a second look at that. For long-distance telephone, it will be necessary to have a flexible policy, and according to the requirements, more of these will have to be given. I am having a look at that. I am not in a position to spell out what exactly that policy decision is. But long-distance telephone is one of the cardinal elements in our expansion scheme. This is all I have got to say. We are having in post-offices. An extra-departmental post office or a sub-office means working for 3 hours or 4 hours. In Andhra, for example, an attempt was made to put it in some shop there and make it available. I find that my income from that area is four times the income from the other one because it works for a longer time and more people go there. That is more serviceable. These are the different aspects which are to be experimented about and which we are experimenting. This is what I have to say about that.

Coming to postcard and other things, you will kindly realise that it is now becoming a losing proposition. (*Interruptions*) For every postcard we are losing 18.5 np. For every inland letter, I am losing 12 np, because my printing charge is more.

SHRI R. K. MHALGI: What do you mean by 'losing'? Government has to do certain things, Government has a certain obligation to discharge towards the poor people.

SHRI C. M. STEPHEN: Does everybody know that? That is why I am saying. I am not coming to put a charge of one rupee on that. I am only saying that, in carrying on this service, on the postcard business the Department is losing Rs. 17 crores, on the inland letter we are losing Rs. 11 crores.

Do you know that a registered newspaper has to give only two nP? For me to manufacture that stamp, it costs three and a half nP. It will be better for me to say, 'I will take your thing free' because I need not lose one and half naya Paisa on this. Why should I lose?

SHRI R. K. MHALGI: Do that. (*Interruptions*)

SHRI C. M. STEPHEN: If the major newspapers can distribute their newspapers giving 33 per cent as commission to the distributing man, to me who is taking it from Delhi to Cape Comorin why should they not give a little more? Anyway this is the matter. I am not saying that I am going to increase it...

SHRI R. K. MHALGI: Don't do it *Kripaya*.

SHRI C. M. STEPHEN: But the question is that the postal section is running into a loss, and it is gradually increasing. Two years ago the loss was Rs. 3 crores. The next year it was Rs. 29 crores and this year it is going to be Rs. 35 crores. I mean that it is being sustained by the telecommunications system. If you are going to expand in a big way, how long can this loss be sustained is a matter which has to be considered. Not that any step is going to be taken....

PROF. N. G. RANGA: It has been so ever since it was established.

SHRI C. M. STEPHEN: I am just putting it across—not that any step is being taken towards that end.

Again my sister, Shrimati Vidyavati Chaturvedi was saying that the charges for the telephones are very high. We have raised the charge from 30 to 40 paise in this Budget for 1750

[Shri C. M. Stephen]

to 5000 calls. Here you must understand that to maintain one telephone, it costs me Rs. 1800. I am collecting Rs. 200 to Rs. 250 as rental. If somebody is dialling only 250 calls, I have to give him the telephone sustaining a loss of Rs. 1200....

SHRI R. K. MHALGI: What is this calculation?

SHRI C. M. STEPHEN: Rs. 1000 only if the telephone is maintained. The calculation is perfect. I cannot give you the calculation on board now. The maintenance charge is Rs. 1800 total. That includes salary of the staff and everything. If a person does not ring the minimum, he gives me only Rs. 800 to Rs. 1000 in that situation and the rest is a loss. These are certain financial aspects which the Parliament would do well to know. I am just spelling it out.... (*Interruptions*)

AN HON. MEMBER: Why don't you recover the arrears of Rs. 33 crores?

SHRI C. M. STEPHEN: Rs. 33 crores is a continuing arrear at any particular moment. It is a service. You get the service and we send you the bill. Therefore, at any point of time, there will be about Rs. 30 to 33 crores of arrears. You must understand 90 to 95 per cent is being collected. The other one is there. It is not going to remain uncollected. In some odd cases collection becomes difficult. A very near friend of mine owes me Rs. 80,000 and the collection is difficult.

SHRI R. K. MHALGI: Near and dear. Why is not his name being mentioned?

SHRI C. M STEPHEN: A very near and dear friend of both of us. I do not want to mention the name.

As far as our efforts are concerned. we are collecting. We are ruthless. We can collect. There was a time when bills were not coming. But it has become a thing of the past. Now bills are coming on time and the collection is being insisted upon...

SHRIMATI PREMILA DANDAVATE: Bills are rising enormously.

SHRI C. M. STEPHEN: Calling also may be very exorbitant. I do not know.

About stamps, it was mentioned about Shivaji and Chandrasekhar Azad. For Shivaji Maharaj we have issued 3 or 4 commemorative stamps. Chandrasekhar Azad stamp has to be issued this year. This was the 50th year of his death anniversary. On this anniversary, Bhagat Singh and all these martyrs together came. Therefore, we took a decision that rather than for each individual, in memory of all of them we will issue one commemorative stamp as martyrs' stamp. A martyrs' stamp we did issue earlier. We need not have issued again. But as Bhagat Singh, Raj Guru, Sukh Dev and Chandrasekhar Azad, all these martyrs came together, to commemorate that we thought we must pay our homage and the martyrs' stamp had to be issued and this was for Chandrasekhar Azad also and for everybody together this stamp was issued.

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और महाराजा अग्रसेन के बारे में भी निवेदन किया गया है । बहुत मांग है ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य : सावित्री बाई फुले के की भी बहुत मांग है—

This is 150th Year of the first woman who fought for women's rights.

स्कूल वगैरा भी शुरू किया, इसके बारे में मैंने टर भी लिखा है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : आपका चिट्ठी मिला है । (व्यवधान)

Sir, from different parts of the country great men who enriched our culture, civilisation and freedom movement they are there. Our capacity is very limited. We can altogether issue only 40 stamps in a year. For personalities we have reserved 7 stamps in a year. That is on the high side. No country does that. They put forth a stamp in a different manner altogether depicting their culture, depicting their architecture, depicting their topography and depicting their birds. We have this year issued stamps for the 'Brides of India' which are selling like hot cakes abroad. We have issued beautiful stamps for 'Brides of India.'

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE: Burning brides!

SHRI C. M. STEPHEN: We have now started a series of stamps—Men to depict the freedom struggle of our country. That is a separate series. This series of stamps taken together will give us a picture of the total freedom struggle. We are now publishing this series of stamps one after the other. It is going to be issued. In this series all these can be taken care of. You kindly leave this to us to do it. This is what we have to say. But we cannot go on multiplying stamps like that. As far as 1980-81 is concerned our schedule is full.

Sir, one point was raised against postal stationery. In an explosive measure the demand has come up. The Nasik Press has got to give us. It has limited capacity. Certain reforms have been effected In one sheet whereas earlier 50 stamps could be given now we have reduced the size of the stamps so that 70 stamps can be given and, as such, the total number could be increased. Franking machines have been introduced in a big way. Major houses will have to use franking machines and we are giving them for that a concession of 1.5 per cent to 2 per cent if they are using franking machines. Over and above that the Nasik Security Press is establishing a press in Hyderabad which will take care of the additional requirements. Mr. Parulekar asked me about that. I never said that it will never happen. I said that it will happen. It is happening. The Hyderabad press is coming up. So, Sir, different steps are being taken but there is tightness because the demand has come in a very big way.

Sir, when I am told of the stamps shortage I am extremely happy because it means there is a harvest for me to take. Earlier I was not able to meet the demand but now the demand is being met. Equitable distribution is being arranged.

Sir, I think I have covered most of the points. I just want to give picture of development that is before us in 1980—85 period. We are having a leap-forward quantitatively. Switching capacity achievement as on 1-4-1980 was 23.36 lakh lines. In this Plan period another 15 lakh lines will be given. U/G cables 117.48 lakh pair kilometres. To this another 78 lakh will be added. Subscribers' telephone Stn. 26.16 lakh to which another 18 lakh will be added on. Long distance switching telephone automatic exchanges are 18 today. Another 40 will be added on. Tax capacity lines 40,300. Another 94,770 capacity will be added on. In large areas, it is above 70 per cent of the present capacity. In some cases, more than 100 per cent will be added to the capacity which we have got today. It is a very tight programme. It is not so easy to do it because to instal an exchange they have to put up a building, instal the equipment, etc. It is a big exchange. It takes about 6 to 7 years before it is completed. It takes quite a lot of time. So, it is a very tight programme. For that we have to set up a Civil Wing. Now, the Civil Wing is coming up and we have to strengthen the Civil Wing and it will take up the task. I am absolutely confident that we will be able to start that. Now, in 1980—82, certain important events are taking place. One is the Madras-Penang Submarine Cable which we have already laid will come into operation. Once the Madras-Penang Submarine link comes into operation it gets connected with the Eastern parts of the world, a

[Shri C. M. Stephen]

large number of countries and from there up to Australia this Submarine cable will go across. And we will also get linked up with INTELSAT which is operating in the Pacific and through that we will be able to get on the United States and the different cities in the United States to which we do not have direct access today. It is a great break-through that is coming across.

Then, this year you will see the launching of the Indian satellite. By the end of 1981 or at the beginning of 1982, two Indian satellites will be put on the orbit and the Earth Stations are almost ready. 28 Earth Stations are stationery and 4 Earth Stations are mobile which will be taken to whichever place that has got to go to give connection. That will enable the major cities in our country to get connected without interruptions, wihout murmuring and without any voice just coming in across and then it will become absolutely easy.

In 1981-82, TROPOSCATTOR communication link with the USSR will be commissioned. That is a different system altogether and through Tashkant to Moscow this connection will be completed. In this year itself, there is another system, that is, INMARSAT which will connect our ships on the oceans from the shore. The earth station for that, at the outer Bombay, is being built. Everything is ready and the ships have got to approve the design and standardisation and a major part of this work will get through.

Then another thing which we have is the computer station in the metropolitan cities for dealing with the subscribers' complaints, subscribers' enquiries and these are necessary. It will not come across in 1981-82. But the preliminaries will be over and we will be able to get this computer service also into the plan.

Sir, this 1980-81 period is a period of great development technologically because the digital electronic system is coming up. In different aspects, it is coming up; local system is coming, trunk system is coming up, the transmission system is coming up. These important things are coming up. We are starting our production in a bit way. In 1981-82, we will have started, not exactly produced, started setting up the 2 lakh lines of new production capacity in Rae Bareily. In 1981-82, we will have again gone a long way in expanding our production capacity in Palghat for digital electronic trunk exchange. The manufacture of this will have gone a long way. A global tender was ready and I think it has already been floated and it is now available which is to be purchased. For the electronic exchange, one million per year, in the first factory with 5 lakhs of production capacity, the efforts are being taking in a very expeditious manner. This means a break-through in all these areas.

We are switching on to the electronic system, not because the cross-bar is obsolete and I do not subscribe to this view. The cross bar is there and will be there and it is still there in different parts of the world. Large parts of the world are still being sustained on cross bar. The eletronic switch equipment has not come up to the final formation. We are getting ready to take our own. This is coming on. One thing on which I am very clear is that unlike in the other countries, we are at the beginning of the Telecommunication expansion here. We have only 23 lakhs of lines here in this huge country. It is only the beginning of it. By about 1990, about 80 lakh of connections will have to be given. That is the total expansion that is coming. My own assessment is that it will be much more than that. Only a small part of it will be crossbar; we are not going to uproot whatever crossbar

is there; the rest of it is coming as electronic lines. Therefore, I can clearly see that by 1990, we will be the country, compared to any other country, which will have the larger proportion of electronic systems in the telecommunication system than any other country. Electronic is coming in a big way, because all the additions will be in electronics. Electronics is coming in a big way. Our production capacity of one million per year is going to be fed into the system, which will gradually convert our present system into electronic system. That will make our system efficient. Even after the electronic system comes in, in 1990 when a debate takes place in this house, the criticism will be the same as we had today, wrong connections, wrong bills, and all that. That is the type of telecommunication system; we will have to live with this and carry on.

I have one word more and I have done. I must pay my compliments to the engineers who are working in the department. They have developed a research and development wing. They have made a great breakthrough. Many things that we are having today are because of the break-through they had. But we feel, we will have to purchase technology of the highest order from abroad and absorb it. Even absorbing technology itself means a certain technological capacity. You cannot absorb the electronic system unless you have the technological capacity. We have built up this group and we are still building this up gradually. We have got the competence. The Communication Ministry does not mean postcards, inland letters and telephones only. It has got a huge coverage in the other areas. We have got our factories working. We are producing whatever we want. The telephonic instrument being produced presently is not of a high quality. The quality is being upgraded. Some collaboration arrangement is being brought about, so that we have the best of telephone instrument. When that comes in, I am sure, most of the complaints, will evaporate.

We have got our postal system, our banking system, our insurance system and many States are now taking our services for collecting their taxes, collecting their vehicle taxes, collecting their electricity bills. All this is because we are so spread out throughout this country. Our effort has got to be to make that unit viable. Today, it is not viable; it has got to be made viable.

My heart is certainly with the extra-departmental people, but you must understand the philosophy behind the extra-departmental system. What are the questions, if the extra-departmental people are to be treated as full-paid workers? Mr. Deputy-Speaker is staring at me, because he has got an interest in these people. But let me tell the fact. The fact of the matter is that they have to be treated as agents and they had to have their own source of income. That is one of the condition, but that was not how it was done. I was warned that I should not quote America and other foreign countries. Mr. Mhalgi warned me. I submit to that warning, and, therefore, I am not quoting them. The fact remains that we have 2.5 lakh people and for those 2.5 lakh people to raise resources would mean very much. Therefore, our effort has got to be to make those units viable in some other method. How exactly that can be done is a matter I am just going into. To the extent it is possible, it has got to be done. After we assumed charge of this Ministry, we gave them bonus. What they were getting was revision once in two years. A higher revision was given to them. Then, I have ordered that this revision must be done every year. Now, every year they are getting a revision. In the course of this one year, their emoluments, I think, have gone up by about Rs. 30 to Rs. 50. This

[Shri C. M. Stephen]

figure may not be very accurate, but it has gone up to that extent. We are very much concerned about them. They do considerable service for the postal department.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Since you have mentioned my name, I would like to make one request. You are giving dearness allowance to all Government employees and even to pensioners? Why can't you give some dearness allowance to them instead of this revision every year and making all these calculations. You can give them dearness allowance which has been recommended by the Boothalingam Committee also. You may consider that.

SHRI C. M. STEPHEN: That is a disqualification.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): Sir, make this request as direction from the chair.

SHRI C. M. STEPHEN: Anyway, Sir, it is a very complicated question.

SHRI R. K. MHALGI: Question is simple. Reply may be complicated.

SHRI C. M. STEPHEN: Reply can be simple. Question is complicated. Anyway, as I said, Sir I can understand the difficulty. My heart is with them, because I have been with them all my life. I understand that what my present position today is. I make use of the sacred floor of this House to make an appeal to all people who are working in the Department to fully realise the national commitment they have, because serving the people is the assignment that everyone of us has, particularly, in this Department. The Postal Department has a tradition of devotion, commitment and earnestness in the job. Not that it has gone. It is still there. It has got to be revived in full measure. Taking care of their problems is my concern; taking care of the people must be their concern. And if that happens everything will improve.

I thank all the Members who spoke in this debate, for the mildness with which they spoke, for the sweetness with which they spoke. Mr. Mani Ram Bagri was extremely concerned about me. His argument was simple, Sir. He knew that the Department is difficult to improve. He does not want me to remain and to get my name spoiled. He said that this Department will never improve; therefore you get out of it. That is what he said not that I must resign. That is what he meant. But I must assure him I can remain here and improve this department and come here in the next year with a better tone, with a better result and greater services to the people and a greater record established.

SHRI VIRBHADRA SINGH: One clarification, Sir. The Hon. Minister has not mentioned about the P&T Circle in Himachal Pradesh which I had mentioned.

SHRI C. M. STEPHEN: P&T Circle was at one time sanctioned and there was some difficulty about the Office. It is not a question of our not being able to pay. We don't take any office free. We don't want anything free. But we must have sufficient space for accommodation for our Staff. We don't want to take people in a place like Simla or Himachal Pradesh. Taking the Staff there and not being able to give them accommodation is the problem. I have written to the Chief Minister if this problem can be tackled, then the Order remains. I have not cancelled the Order. It remains.

DR. KRUPASINDHU BHOI: About Orissa, lower priority has been given for automatisation. Out of 13 district Headquarters, only one headquarter has got the automatic exchange. About the Bhubaneswar Electronic Exchange I must congratulate the Minister.

SHRI C. M. STEPHEN: I have divided my speech into two general issues and an attempt to project the future. The other issues were raised as in Mr. Mhalgi's Cut Motions. May be they did not focus it up. But I can assure you that all the issues will be examined and all of you will get a reply on all the questions raised.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: In my speech I referred to the import of machinery for the Rae Bareily unit at the cost of Rs. 36 Crores especially when our Engineers have made provision for the other crossbar system. There is a reference to it in the Press and there is a criticism also. I would like you to answer with reference to that.

SHRI C. M. STEPHEN: Our Engineers have developed an Indian Crass-Bar project. ICB we say. The conflict was between whether we must have that ICB or some other. It is this ICB that we have adopted. ICB design we have. We do not have the productionsing technology. This is our difficulty with Indian system not only in tele-communication. In designing we are A Class; in software we are first class. In productionising capacity we have not come up to the standard. We have got to depend on other countries. Here also the design is perfectly all right. For productionising we have got to take the aid. We accepted the Belgian because this ICB is a developed system of the Pentaconta which we had. The technology of the Pehtaconta belongs to the Belgian company. There fore we have to go to them. It was in the quotation. I don't remember the figure exactly. How many crores of rupees and all that—I don't exactly remember. A machinery was contemplated, to some extent for exchange transections. And a greater indigenization compared to the others was here. Therefore, we accepted this in preference to the Swedish system, viz. Ericcson. This is the ICP. This is not the foreign system. This is ICP; our engineers developed it. But our engineers said: "For productionizing it, we want a collaboration." And the collaboration from the parental firm was accepted. They are coming forward. And, therefore, when we purchase that, we will have to pay the money. And the money payment is there... (*Interruptions*)

SHRI R. K. MHALGI: What about the parallel post office system? That is the question I had put very precisely.

SHRI C. M. STEPHEN: About parallel post office it must be said that it does not come under my Ministry. Somebody is doing it. Technically, anybody carrying a letter to somebody is doing a postal function. You also can come under it. But is was there; it was discovered and the Police reported to us that there was a gang operating like this for their smuggling activities Rather than putting things through the Postal Service, they were makig some arrangements to take them across—partly parcel and partly letter. This was going on in this manner The Police is investigating. This does not impinge very much on us, although technically it violates the Postal Act.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If the House agrees, I shall put all the Cut Motions together to the vote of the House.

Cut Motions Nos. 1 to 57, 80 to 140, 155 to 225 and 252 to 301 were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants in respect of the Ministry of Communications to the vote of the House.

The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to *complete* the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during

the year ending the 31st day of March 1982 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands No. 14 to 18 relating to the Ministry of Communications."

The motion was adopted.

Demands for Grants, 1981-82 in resspect of the Ministry of Communications Voted by Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 13-3-1981		Amount of Demand for Grant voted by the House	
1	2	3		4	
		Revenue	Capital	Revenue	Capital
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
MINISTRY OF COMMUNICATIONS					
14.	Ministry of Communications	52,70,000	2,69,[illegible]	2,63,50,000	13.45,[illegible],000
15.	Overseas Communications Service . . .	3,56,36,000	4 46 77,000	17,81 81,000	17,77,83,000
16.	Posts and Telegraphs—Working Expenses .	159,46,35,000		7[illegible]7,31,74,[illegible]	..
17.	Posts and Telegraphs—Dividend to General Revenues, Appropriation to Reserve Funds and Repayment of Loans from General Revenues	42,82,22,000		214,11,12,000	
18.	Capital Outlay on Posts and Telegraphs . .	..	85,33,46,[illegible]	..	426,67,27,000

17.34 hrs.

*DEMANDS FOR GRANTS, 1981-82—*contd.*

MINISTRY OF LABOUR

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House iwll now take up discussion and voting on the Demands Nos. 65 and 66 relating to the Ministry of Labour, for which 4 hours have been allotted.

Hon. Members whose cut motions to the Demands for Grants have been circulated, may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move.

A list showing the serial numbers of cut motions desired to be moved will be put up on the Notice Board shortly. In case any Member finds any discrepancy in the list he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table without delay.

Motion moved:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the Fourth Column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to *complete* the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1982, in respect of the heads of demands entered in the Second Column thereof against Demands Nos. 65 and 66 relating to the Ministry of Labour."

*Moved with the recommendation of the President.